घटती घटना

सत्य के साथ...जनहित में बात...

www.ghatatighatana.com अम्बिकापुर,वर्ष 22, अंक - 208- शनिवार 30 - मई 2026,पृष्ठ - 8 मूल्य 2 रूपये RNI Reg.No.- CHHHIN/2004/15050,डाक पंजीयन. क्रं. 13/Surguja DN/ 2026-2028

महाराष्ट्र में जहरीली शराब से 15 की मौत,8 आरोपी गिरफ्तार

सीएम ने कहा...पूरे इकोसिस्टम की कमर तोड़ दी जाएगी...

पुणे,29 मई 2026। महाराष्ट्र के पुणे और पिंपरी-चिंचवाड़ इलाकों में जहरीली शराब पीने से करीब 15 लोगों की मौत हो गई है,जबकि कई अन्य गंभीर रूप से बीमार बताए जा रहे हैं। इस भयावह घटना के बाद राज्य और जिला प्रशासन में हड़कंप मच गया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मामले पर संज्ञान लेकर 8 संदिग्ध आरोपियों की गिरफ्तारी की पुष्टि कर बताया है कि पूरे अवैध शराब के इकोसिस्टम का पता लग गया है,जिस पर आगे कड़ी कार्रवाई की जाएगी। यह चौंकाने वाली घटना पुणे के काले पड़ल, हडपसर और पिंपरी-चिंचवाड़ के दापोडी,फुगेवाड़ी जैसे इलाकों से सामने आई है, जहां लोगों ने अवैध रूप से निर्मित जहरीली शराब का सेवन किया। जानकारी के अनुसार, जहरीली शराब का सेवन करने वाले लोगों की हालत अचानक बिगड़ी,उनके मुंह से झाग निकलने लगा और इलाज मिलने से पहले ही कई लोगों ने दम तोड़ दिया। पिंपरी-चिंचवाड़ के दापोडी और फुगेवाड़ी में आठ,जबकि पुणे के काले पड़ल में तीन और हडपसर में दो लोगों की मौत हुई। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि इस अवैध और स्पिरिट-युक्त शराब को योगेश वानखेड़े नामक व्यक्ति ने तैयार किया था,इस जहरीली शराब को पुणे और पिंपरी-चिंचवाड़ के विभिन्न इलाकों में बेचा गया था। वानखेड़े कथित तौर पर अवैध शराब कारोबार से जुड़ा है और उसके खिलाफ पहले भी कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। पुलिस ने मुख्य आरोपी योगेश वानखेड़े का गिरफ्तार किया है। मुख्यमंत्री फडणवीस ने मामले की गंभीरता को देखकर पुलिस

को त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। उन्होंने बताया कि मामले में अभी तक 8 संदिग्ध आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और पूरे अवैध शराब के इकोसिस्टम का पता लग गया है,इसके बाद इस पूरे इकोसिस्टम की कमर तोड़ दी जाएगी। पिंपरी चिंचवाड़ पुलिस के डीसीपी संदीप अटोले ने पुष्टि की है कि सात लोगों की मौत हुई है और तीन घायल अस्पताल में उपचाराधीन हैं,जबकि आठ आरोपियों से पूछताछ जारी है। लोकल नागरिकों में फुगेवाड़ी जैसे इलाकों में अवैध हाथभट्ठी और देशी शराब के अड्डों के धड़ल्ले से चलने को लेकर भारी आक्रोश है। हालांकि, शुरुआत में दापोडी पुलिस ने जहरीली शराब से हुई मौतों की बात को अफवाह बताकर दावा किया था कि ये सभी मौतें अलग-अलग और स्वतंत्र कारणों से हुई हैं। यह बयान पुलिस की जांच पर सवाल खड़े करता है,खासकर तब जब मुख्यमंत्री फडणवीस ने स्वयं इकोसिस्टम की पहचान और गिरफ्तारी की बात कही है। पुलिस अब मामले के सभी पहलुओं की गहन जांच कर रही है और घायलों का इलाज जारी है।

यूपी में निर्माणाधीन पुल का स्लैब गिरा,6 की मौत

अफसर बोले...आंधी-बारिश के चलते हादसा,3 मजदूरों को बचाया गया

हमीरपुर,29 मई 2026। यूपी के हमीरपुर में बेतवा नदी पर बन रहे निर्माणाधीन पुल का स्लैब शुक्रवार देर रात 2 बजे गिर गया। हादसे में 6 मजदूरों की मौत हो गई। स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स ने मलबे में फंसे 3 मजदूरों को निकाला। साढ़े 7 घंटे तक रेस्क्यू ऑपरेशन चला। मौसम विभाग के मुताबिक, हमीरपुर में देर रात 70-80 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी चली थी। हादसा शहर से 25 किमी. दूर ललपुरा इलाके में हुआ। मृतकों में 4 बांदा और 2 हमीरपुर के रहने वाले थे। प्रत्यक्षदर्शी सुरेश कुमार ने बताया- पुल पर दो शिफ्ट में काम होता है। जिस वक्त आंधी आई,पहली शिफ्ट के लोग पुल के नीचे थे,जबकि दूसरी शिफ्ट के 7 मजदूर पुल पर काम कर रहे थे। उनमें मैं भी था। आंधी से बचने के लिए हम लोग पुल पर लेट गए। इसी बीच हादसा हो गया। उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम पुल का निर्माण करवा रहा है। इसकी लागत 90 करोड़ रुपए है। 700 मीटर लंबा दो लेन का ब्रिज मोराकांड से कुरारा गांव के बीच बनाया जा रहा है। इसका निर्माण मार्च 2024 में शुरू हुआ था। दिसंबर 2026 तक इसे पूरा किया जाना है।

सहायक अभियंता निलंबित, डीपीएम के खिलाफ विभागीय कार्रवाई के निर्देश

यूपी ब्रिज कारपोरेशन के एमडी धर्मवीर सिंह ने बताया...मामले में प्रथम दृष्टया सहायक अभियंता गजेंद्र कुमार चौधरी को निलंबित किया है। डीपीएम दिलीप कुमार

हमीरपुर हादसे पर मुख्यमंत्री योगी ने जताया शोक... मृतकों के परिजनों को पांच-पांच लाख की आर्थिक मदद की घोषणा...

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हमीरपुर जिले में बेतवा नदी पर निर्माणाधीन पुल का स्लैब ढहने में श्रमिकों की मौत पर गहरा शोक प्रकट किया है। मुख्यमंत्री ने मृतकों के आश्रितों को पांच-पांच लाख रुपये तथा घायलों को पचास-पचास हजार रुपये की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। हादसे में छह मजदूरों की मौत हो गई और अभी कुछ और मजदूरों के दबे होने की आशंका के चलते बचाव कार्य चल रहा है। मुख्यमंत्री योगी ने हादसे को अत्यंत दुःखद एवं हृदयविदारक बताते हुए मृतकों के परिजनों के प्रति गहरी संवेदना प्रकट की है। मुख्यमंत्री ने मृतकों के परिजनों को सरकार की ओर से पांच-पांच लाख रुपये की सहायता पहुंचाने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने गुरुवार देर रात कई जिलों में तेज आंधी-तूफान, बारिश और आकाशीय बिजली से भारी तबाही का भी संज्ञान लेते हुए सभी जिलाधिकारियों को बचाव कार्य तेज करने, नुकसान का आकलन करने और राहत राशि जल्द जारी करने के निर्देश दिए हैं।

के खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू की गई है। उन्होंने बताया कि मामले में विभागीय जांच के लिए कमेटी गठित की है। जांच कमेटी में संयुक्त प्रबंध निदेशक, मुख्य परियोजना प्रबंधक (डिजाइन) और मुख्य परियोजना प्रबंधक,कानपुर शामिल हैं।

हादसे के जान गंवाने वाले गंगाचरण दो दिन पहले ही हमीरपुर गए थे : हादसे के जान गंवाने वाले गंगाचरण (26) पुत्र शोभरन सिंह निवासी भूरागढ़ दो भाइयों में बड़े थे। परिवार में उनके छोटे भाई राजीव (20) हैं। परिजनों के मुताबिक, गंगाचरण ने कक्षा 8 तक पढ़ाई की थी। वह करीब दो महीने पहले घर लौट आए थे, लेकिन परसों ठेकेदार का फोन आने पर दोबारा काम के लिए बांदा से हमीरपुर चले गए थे। परिजनों ने बताया...उन्हें सूचना मिली थी कि तेज तूफान के दौरान निर्माणाधीन पुल का हिस्सा गिर गया, जिसमें उनका भतीजा पप्पू भी दब गया। घटना की जानकारी मिलने के बाद परिवार के सदस्य सुन यादव, मनोज यादव और पंकज यादव मौके के लिए रवाना हुए। मृतक की उम्र करीब 26 वर्ष बताई जा रही है।

हादसे में जान गंवाने वाले सभाजीत के परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल

हादसे में जान गंवाने वाले मृतक सभाजीत यादव (25) पुत्र नीलकंठ यादव इंटरमीडिएट पास थे। तीन भाइयों में सबसे बड़े थे। परिवार में उनके छोटे भाई अमन (23) और अमित (21) हैं। हादसे के बाद परिवार में कोहराम मचा हुआ है। मृतक सभाजीत यादव के चाचा राम बाबू ने बताया कि सभाजीत करीब सात-आठ दिन पहले काम करने के लिए हमीरपुर गया था। इससे पहले भी वह वहां काम कर चुका था। गर्मी अधिक होने के कारण दिन में काम बंद कर दिया गया था और ठेकेदार की ओर से रात में ओवरटाइम कराकर निर्माण कार्य कराया जा रहा था। रात में ही मजदूर काम करते थे। राम बाबू के मुताबिक,काम के दौरान अचानक तेज तूफान आ गया। इसी दौरान निर्माणाधीन ढांचा गिर गया और कई मजदूर उसकी चपेट में आ गए।

असम-मिजोरम सीमा पर 18 करोड़ की याबा टैबलेट जब्त,एक गिरफ्तार

सिलचर (असम),29 मई 2026। असम-मिजोरम सीमा पर सुरक्षा बलों ने बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 18 करोड़ रुपये मूल्य की याबा टैबलेट जब्त की है। इस मामले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने शुक्रवार को इसकी जानकारी दी। पुलिस के अनुसार, अवैध मादक पदार्थों की तस्करी की गुप्त सूचना मिलने के बाद सुरक्षा बलों ने बीती रात असम-मिजोरम सीमा पर नाका जांच अभियान चलाया। इस दौरान एक संदिग्ध वाहन (एएस12यू7746) को रोककर उसकी तलाशी ली गई। स्वतंत्र गवाहों की मौजूदगी और पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी के बीच वाहन की जांच करने पर 60 हजार संदिग्ध याबा टैबलेट और एक मोबाइल फोन बरामद हुआ। बरामद सामग्री को तत्काल जब्त कर लिया गया। अधिकारियों ने बताया कि डीडीके किट से जांच करने पर बरामद टैबलेट में मेथामफेटामाइन होने की पुष्टि हुई है। पुलिस ने वाहन चालक को मौके से गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपित की पहचान मणिपुर के चुराचांदपुर जिले के जाओलेन कुम्बीपुखरू गांव निवासी नगामलेन (44) के रूप में की गई है। अधिकारियों के मुताबिक, जब्त मादक पदार्थों की अंतरराष्ट्रीय काले बाजार में अनुमानित कीमत करीब 18 करोड़ रुपये आंकी गई है।

कर्नाटक में सत्ता परिवर्तन के बाद तेज हुई राजनीतिक हलचल..दिल्ली पहुंचे सिद्धारमैया,मंत्रिमंडल गठन पर मंथन

नई दिल्ली 29 मई 2026। कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के एक दिन बाद पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया शुक्रवार को दिल्ली पहुंचे,जहां उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की। माना जा रहा है कि बैठक में कर्नाटक के नए मंत्रिमंडल के गठन और सत्ता हस्तांतरण के बाद राजनीतिक संतुलन बनाए रखने पर चर्चा हुई। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सिद्धारमैया ने पार्टी नेतृत्व के समक्ष कई महत्वपूर्ण सुझाव और मांगें रखीं। इनमें उनके पुत्र यतींद्र सिद्धारमैया को नए मंत्रिमंडल में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दिए जाने का मुद्दा भी शामिल बताया जा रहा है। हालांकि कांग्रेस नेतृत्व की ओर से इस संबंध में कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है। इस बीच राज्यपाल द्वारा सिद्धारमैया का इस्तीफा स्वीकार किए जाने के बाद कर्नाटक में नई सरकार के गठन की प्रक्रिया तेज हो गई है। पार्टी सूत्रों के अनुसार उपमुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार अगले सप्ताह मुख्यमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं।

अगले दो वर्षों में देश का सीमावर्ती क्षेत्र दुश्मनों से हमेशा के लिए सुरक्षित हो जाएगा : अमित शाह

बीएसएफ के 60वें वर्ष पर अमित शाह का विजन,बनेगा 'चतुष्कोणीय सुरक्षा ग्रिड'

भुज,29 मई 2026। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात के भुज में कहा कि केंद्र सरकार सीमा सुरक्षा को अभेद्य बनाने के लिए तेजी से काम कर रही है और अगले दो वर्षों में देश का सीमावर्ती क्षेत्र दुश्मनों की बुरी नजर से हमेशा के लिए सुरक्षित हो जाएगा। उन्होंने कहा कि आधुनिक तकनीक, मजबूत सुरक्षा ढांचे और बीएसएफ जवानों के पराक्रम के बल पर भारत की सीमाओं को और अधिक सशक्त बनाया जा रहा है। कच्छ के भुज क्षेत्र में आज सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के जवानों को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री शाह ने कहा कि सरक्रीक और भुज क्षेत्र में बीएसएफ के जवान चट्टान की तरह सीमा की रक्षा कर रहे हैं। उनके साहस, समर्पण और सतर्कता के कारण इस क्षेत्र के लोग सुरक्षित

जीवन जी रहे हैं। उन्होंने कहा कि जवानों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है और इसके लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि सरकार ने सीमा सुरक्षा के लिए बजट की कोई कमी नहीं रहने दी है। आधुनिक तकनीक के उपयोग पर विशेष जोर दिया जा रहा है, जिससे सीमा सुरक्षा तंत्र को मजबूत करने में सफलता मिली है। उन्होंने बताया कि सीमावर्ती क्षेत्रों में वॉच टावरों का निर्माण किया गया है और कई बॉर्डर आउट पोस्ट (बीओपी) को ग्राउंड लेवल से ऊपर उठाकर अधिक सुरक्षित बनाया गया है। इन प्रयासों से जवानों की कार्यक्षमता बढ़ी है और निगरानी व्यवस्था अधिक प्रभावी हुई है। उन्होंने कहा कि बीएसएफ अपनी स्थापना के 60 वें वर्ष में प्रवेश कर चुकी है। इस अवसर पर सीमा सुरक्षा की अवधारणा को नए सिरे से विकसित करने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने बताया कि आने वाले समय में 'चतुष्कोणीय सुरक्षा ग्रिड' तैयार किया जाएगा और केवल सीमा सुरक्षा की जगह 'टेरिटोरियल सिक्योरिटी' यानी क्षेत्रीय सुरक्षा का नया मॉडल लागू किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि इस नई व्यवस्था में बीएसएफ के साथ-साथ स्थानीय नागरिक, सिविल प्रशासन, स्थानीय पुलिस और सेना भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। इससे सुरक्षा व्यवस्था अधिक मजबूत और व्यापक बनेगी। उन्होंने कहा कि सीमा सुरक्षा को जनभागीदारी से जोड़ने का यह प्रयास देश की सुरक्षा को नई दिशा देगा।

सुप्रीम कोर्ट में नीट पेपर लीक मामले की सुनवाई

कोर्ट ने कहा...जवाबदेही तय होना जरूरी....

नई दिल्ली 29 मई 2026। नीट प्रश्न पत्र लेकर मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत को बताया कि पूर्व इसरो चेयरमैन के नेतृत्व वाली कमेटी ने अपना जवाब सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कर दिया है। यह सुनवाई जस्टिस पी. एस. नरसिम्हा और जस्टिस आलोक अराधे की बेंच द्वारा की जा रही है। याचिकाओं में मांग की गई है कि परीक्षा को नए सिरे से कराने के लिए एक हाई पावर कमेटी गठित की जाए और

नीट परीक्षा सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की निगरानी में कराई जाए। पूर्व इसरो चेयरमैन के. राधाकृष्णन ने कहा कि एनटीए को मजबूत करने की सलाह दी गई थी और कई सुधार लागू किए गए हैं। उन्होंने यह भी आश्वासन दिया कि आगे होने वाली नीट परीक्षा के लिए सभी सुझावों को ध्यान में रखा गया है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि जब तक वास्तविक जवाबदेही तय नहीं होगी,तब तक व्यवस्था में सुधार संभव नहीं है। अदालत ने कहा कि जिम्मेदारी केवल व्यक्तियों की नहीं बल्कि संस्थागत स्तर पर तय होनी चाहिए। कोर्ट ने यह भी कहा कि यूपीएससी जैसी संस्थाओं में ऐसी स्थिति कभी नहीं बनती, इसलिए बाकी संस्थाओं को उससे सीख लेने की जरूरत है।

देश में पेट्रोल-डीजल, एलपीजी,नैचुरल गैस और कच्चे तेल का पर्याप्त स्टॉक

नई दिल्ली,29 मई 2026। पश्चिम एशिया में जारी संकट के बीच केंद्र सरकार ने शुक्रवार को कहा कि देश में पेट्रोल, डीजल, घरेलू रसोई गैस नेचुरल गैस और कच्चे तेल का पर्याप्त स्टॉक मौजूद है। सरकार ने कहा कि सभी रिफाइनरियां भी अपनी पूरी क्षमता से काम कर रही हैं। वहीं,एलपीजी का उत्पादन रिकॉर्ड स्तर पर है,जो लगभग 92 टीएमटी (हजार मीट्रिक टन) प्रतिदिन है। पेट्रोलियम एवं नेचुरल गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने नई दिल्ली में अंतर-मंत्रालयी प्रेसवार्ता में बताया कि एलपीजी का उत्पादन रिकॉर्ड स्तर पर है,जो लगभग 92 टीएमटी (हजार मीट्रिक टन) प्रतिदिन है। किसी भी घरेलू रसोई गैस डिस्ट्रीब्यूटरशिप ने स्टॉक के खत्म होने की शिकायत नहीं की है। कुछ जिलों में खेती की मांग और बदलते बाजार के रुझानों के कारण पेट्रोल और डीजल की बिक्री में असामान्य रूप से बढ़ोतरी देखी गई है, लेकिन सप्लाई स्थिर बनी हुई है। शर्मा बताया कि राज्य सरकारों, केंद्र शासित प्रदेशों और उद्योग संघों को जमाखोरी और कालाबाजारी रोकने की सलाह दी गई है और उपभोक्ताओं से आग्रह किया गया है कि वे ईंधन केवल अधिकृत माध्यमों से ही खरीदें। उन्होंने कहा कि सरकार ने दोहराया है कि ईंधन की उपलब्धता पर्याप्त है और अनावश्यक रूप से स्टॉक जमा करने की कोई जरूरत नहीं है।

ट्विशा शर्मा मौत मामले में कोर्ट ने सास गिरिबाला और पति समर्थ को पांच-पांच दिन की सीबीआई रिमांड पर भेजा

भोपाल,29 मई 2026। अभिनेत्री और मॉडल ट्विशा शर्मा की संदिग्ध मौत के मामले में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) की विशेष अदालत ने शुक्रवार को

मृतका की सास (रिटायर्ड जज) गिरिबाला सिंह और पति समर्थ सिंह को न्यायाधीश शोभना भलावे के समक्ष पेश किया। जहां अदालत ने सीबीआई की मांग पर दोनों को 5-5 दिन की रिमांड पर भेज दिया है। दरअसल, सुनवाई के दौरान जांच एजेंसी के वकीलों ने मामले की कड़ियों को जोड़ने और गहन पूछताछ के लिए दोनों आरोपितों की 5-5 दिन की रिमांड मांगी,जिस पर बचाव पक्ष के वकीलों ने कोई आपत्ति नहीं जताई। अदालत ने दोनों की 5 दिन की सीबीआई रिमांड मंजूर कर ली है। समर्थ सिंह पहले से ही सीबीआई की हिरासत में था, जिसकी रिमांड अवधि अब 5 दिन और बढ़ा दी गई है। अदालत में पेशी से पहले समर्थ का जेपी अस्पताल और गिरिबाला सिंह का मैनिट परिसर में मेडिकल चेकअप कराया गया। शुक्रवार को अदालती कार्यवाही के दौरान दोनों आरोपितों को एक ही कटघरे में खड़ा किया गया,जहां मृतका के पिता की ओर से वरिष्ठ वकील सिद्धार्थ लूथरा और गिरिबाला सिंह की तरफ से वरिष्ठ वकील नित्या मौजूद रहीं। सीबीआई इस हाई-प्रोफाइल मामले की परतें खोलने के लिए अब देश की सबसे आधुनिक जांच पद्धतियों का इस्तेमाल कर रही है। सीबीआई सूत्रों के मुताबिक,मामले को सुलझाने के लिए 'टनल व्यू इन्वेस्टिगेशन' तकनीक का सहारा लिया जा रहा है, जिसके तहत ट्विशा के जीवन के आखिरी घंटों का एक वर्चुअल रीक्रिएशन तैयार किया जा रहा है। जांच एजेंसी कैमरों के टाइमस्टैंप, मोबाइल फोन डेटा, वाई-फाई लॉग, कॉल डिटेल रिकॉर्ड (सीडीआर) और टावर लोकेशन का मिलान कर एक सिम्युलेटेड वर्चुअल वॉकथ्रू और ट्विशा का 'डिजिटल अवतार' तैयार कर रही है।

दिल्ली हाई कोर्ट ने 'कॉकरोच जनता पार्टी' के एक्स अकाउंट ब्लॉक मामले में केंद्र और एक्स को भेजा नोटिस,अकाउंट अभी बहाल करने से इनकार

नई दिल्ली,29 मई 2026। दिल्ली हाई कोर्ट ने 'कॉकरोच जनता पार्टी' के एक्स (पूर्व में ट्विटर) अकाउंट को भारत में ब्लॉक किए जाने के मामले में केंद्र सरकार और एक्स को नोटिस जारी किया है। हालांकि,अदालत ने फिलहाल ब्लॉक किए गए अकाउंट को तुरंत बहाल करने का आदेश देने से इनकार कर दिया। यह सुनवाई कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके की याचिका पर हुई, जिसमें उन्होंने अपने व्यंग्यात्मक डिजिटल संगठन के सोशल मीडिया अकाउंट को ब्लॉक किए जाने के फैसले को चुनौती दी है। जस्टिस पुरुषेंद्र कुमार कौरव की पीठ ने मामले की सुनवाई की। अभिजीत दीपके पहले आम आदमी पार्टी (आप) से जुड़े रहे हैं। उन्होंने 15 मई को उस विवाद के बाद 'कॉकरोच जनता पार्टी' की शुरुआत की थी, जो मुख्य न्यायाधीश सुरेश कांत की एक टिप्पणी के बाद सामने आया था। सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश ने कुछ लोगों की तुलना कॉकरोच और परजीवियों से की थी। बाद में 16 मई को मुख्य न्यायाधीश ने स्पष्ट किया कि उनका बयान युवाओं के लिए नहीं, बल्कि फर्जी और बोगस डिग्री लेकर वकालत में आने वालों के लिए था। उन्होंने यह भी कहा कि मीडिया में उनके बयान को गलत तरीके से पेश किया गया।

हार के बाद संभलने की तैयारीः इंडी गठबंधन 6 जून को करेगा बैठक,तय होगी आगे की रणनीति

नई दिल्ली,29 मई 2026। देश की मौजूदा राजनीतिक स्थिति का जायजा लेने और भविष्य की रणनीति तय करने के लिए विपक्षी इंडी गठबंधन आगामी 6 जून को एक महत्वपूर्ण बैठक करने जा रहा है। इंडी गठबंधन की इस बैठक में क्षेत्रीय दलों की कमजोर होती स्थिति और चुनावी सूचियों (वोटर लिस्ट) में गड़बड़ी जैसे गंभीर मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। सूत्रों के हवाले से बताया कि हालिया विधानसभा चुनावों में मिली हार और भाजपा की बढ़ती मजबूती के बीच,ममता बनर्जी की टीएमसी और राहुल गांधी सहित तमाम विपक्षी नेता अब आपसी मतभेदों को भुलाकर 'लोकतंत्र को बचाने' के लिए एकजुट होने की तैयारी में हैं। विपक्षी दलों में यह चिंता लगातार गहरी हो रही है कि आपस में तालमेल और एकता की कमी का सीधा फायदा सत्ताधारी भाजपा को मिल रहा है।

भारत-अमेरिका,अंतरिम व्यापार समझौते के करीब : पीयूष गोयल

नई दिल्ली,29 मई 2026। भारत के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने अमेरिकी व्यापार जगत के प्रतिनिधियों से कहा है कि भारत की अमेरिका के साथ व्यापार समझौते को लेकर जारी बातचीत में''उत्साहजनक प्रगति'' हुई है और दोनों देश इस पर एक अंतरिम समझौते के करीब पहुंच गये हैं। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने अंतरराष्ट्रीय व्यापार जगत के दिग्गजों के साथ बातचीत के दौरान यह जानकारी दी। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री ने 'एक्स' पोस्ट पर बताया कि उन्होंने न्यूयॉर्क में एक गोलमेज बैठक के दौरान 50 से ज्यादा वैश्विक व्यापार और उद्योग जगत के नेताओं के साथ बातचीत की। उन्होंने बताया कि इस कार्यक्रम का आयोजन अमेरिका के न्यूयॉर्क में

स्थित भारत के महावाणिज्य दूतावास ने अमेरिकी-भारत रणनीतिक साझेदारी मंच के सहयोग से किया था।

पीयूष गोयल ने कहा कि गोलमेज बैठक में वैश्विक कारोबारियों के बीच प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत की मजबूत विकास गाथा, सुधार-आधारित कारोबारी माहौल और वैश्विक निवेशकों के लिए बढ़ते अवसरों पर प्रकाश डाला तथा साझा समृद्धि के लिए भारत-अमेरिका के बीच व्यापार, निवेश, नवाचार और आपूर्ति-श्रृंखला से जुड़ी साझेदारियों को और अधिक गहरा करने के तरीकों पर चर्चा की। गोयल ने उद्योग जगत के कई प्रमुखों के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी कीं। मॉर्गन स्टैनली के चेयरमैन एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी टेड पिक के साथ बैठक में उन्होंने भारत में दीर्घकालिक निवेश और संस्थागत साझेदारी को मजबूत करने पर चर्चा की। उन्होंने वारबर्ग पिंकस के चेयरमैन चिप केय के साथ वैश्विक निवेश परिदृश्य और भारत के उभरते आर्थिक अवसरों पर विचार-विमर्श किया। गोयल ने कहा कि एमनील फार्मास्यूटिकल्स के सह-संस्थापक एवं सह-सीईओ चिंटू पटेल के साथ बैठक में भारत के दवा क्षेत्र में निवेश एवं नवाचार को बढ़ाने के अवसरों पर चर्चा हुई। इसके अलावा मास्टरकार्ड के सीईओ माइकल मीबैक के साथ गोयल ने डिजिटल वाणिज्य, डिजिटल सुरक्षा और नयी पीढ़ी की भुगतान प्रणालियों में सहयोग बढ़ाने पर विचार किया। यू एस आई एस पी एफ ने भी एक बयान में कहा कि पीयूष गोयल ने इस बात पर जोर दिया कि निवेशकों का विश्वास,कारोबार की स्थिरता और मजबूत नियामकीय माहौल भारत सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल हैं। इससे पहले 25 से 27 मई के दौरान पीयूष गोयल के नेतृत्व में 150 से अधिक सदस्यों का व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल कनाडा गया था,जहां वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री ने निवेश आकर्षित करने,सहयोग बढ़ाने और प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौते को गति देने के प्रयास किए। उल्लेखनीय है कि अमेरिका का एक प्रतिनिधिमंडल दल 1 से 4 जून, 2026 के बीच भारत के दौरे पर नई दिल्ली आएगा।

संपादकीय

कर्नाटक में परिवर्तन

आखिरकार कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्दरमैया ने त्यागपत्र दे दिया और उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के उनकी जगह आसीन होने का रास्ता साफ हो गया। कर्नाटक में नेतृत्व परिवर्तन की चर्चा लंबे समय से हो रही थी और इसे लेकर खींचतान भी जारी थी,लेकिन कुछ तय नहीं हो पा रहा था। शिवकुमार का दावा था कि 2023 में सरकार गठन के समय सिद्दरमैया और उनके बीच ढाई-ढाई वर्ष तक सत्ता संभालने की सहमति बनी थी,पर कांग्रेस नेतृत्व ने इसकी पुष्टि नहीं की।

अब तीन वर्ष बाद नेतृत्व परिवर्तन होना यह बताता है कि वास्तव में दोनों नेताओं में बारी-बारी से मुख्यमंत्री बनने का समझौता हुआ था और उससे कांग्रेस आलाकमान भी अवगत था। यदि ऐसा था तो फिर छह माह की देरी क्यों हुई? यह प्रश्न कांग्रेस नेतृत्व और विशेष रूप से राहुल गांधी की विफलता को दर्शाता है। इसलिए और भी,क्योंकि कहा जा रहा है कि नेतृत्व परिवर्तन तब सुनिश्चित हो पाया, जब प्रियंका गांधी ने हस्तक्षेप किया। यदि यह सच है तो यह पुराना सवाल फिर से उठेगा कि आखिर राहुल गांधी समय पर फैसला क्यों नहीं ले पाते? ध्यान रहे कि कांग्रेस अध्यक्ष भले ही मल्लिकार्जुन खरगे हों,लेकिन पार्टी के बड़े फैसले राहुल गांधी ही लेते हैं।

त्यागपत्र देने को तैयार हुए सिद्दरमैया ने यह तो माना कि आलाकमान ने जैसा कहा,वैसा किया,पर वे राज्यसभा आने को तैयार नहीं। एक तरह से उन्होंने कांग्रेस नेतृत्व को यह संदेश दिया कि वे संतुष्ट नहीं हैं और अपने हिसाब से राज्य की ही राजनीति करेंगे। हालांकि उनके त्यागपत्र देने पर शिवकुमार ने पैर छूकर उनका आशीर्वाद लिया,लेकिन यह कहना बहुत कठिन है कि दोनों के रिश्ते सामान्य बने रहेंगे और कर्नाटक कांग्रेस में गुटबाजी को बढ़ावा नहीं मिलेगा।

इसकी अनदेखी न की जाए कि इसके पहले बारी-बारी से नेतृत्व करने को लेकर राजस्थान और छत्तीसगढ़ में इसी तरह की खींचतान हुई थी। राजस्थान में अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच ढाई-ढाई साल तक सत्ता संभालने को लेकर तनातनी जारी रही तो छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल और टीएस सिंह देव के बीच। कांग्रेस नेतृत्व न तो इन दोनों राज्यों में अपने नेताओं के झगड़े को सुलझा पाया और न ही यह साफ कर पाया कि उनमें ढाई-ढाई साल तक मुख्यमंत्री रहने का समझौता हुआ था या नहीं?

पंजाब में उसने नवजोत सिंह सिद्धू को संतुष्ट करने के लिए मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह को पद छोड़ने के लिए बाध्य किया तो इसके नतीजे में वहां ऐसी गुटबाजी पनपी कि पार्टी को बुरी पराजय का सामना करना पड़ा। कांग्रेस राजस्थान और छत्तीसगढ़ भी नहीं बचा पाई। कर्नाटक में क्या होगा,यह दो साल बाद होने वाले विधानसभा चुनाव ही बताएंगे।

सुखद है 200 वर्षों का हिन्दी पत्रकारिता का इतिहास

योगेश कुमार गोयल
नजफगढ़,नई दिल्ली

हिन्दी पत्रकारिता की दशा और दिशा

भारत में प्रेस ने लगभग प्रत्येक महत्वपूर्ण अवसर पर अपनी महत्ता सिद्ध की है, फिर चाहे भारत-पाक युद्ध हो या भारत-चीन लड़ाई अथवा अन्य कोई चुनौतीपूर्ण अवसर। यह कहना भी असंगत नहीं होगा कि हिन्दी पत्रकारिता का स्थान इसमें सर्वोपरि रहा है। हिन्दी भाषी समाचारपत्र हों अथवा पत्रिकाएं, उनका देश की बहुसंख्यक आबादी के साथ सदैव विशेष जुड़ाव रहा है और इस दृष्टि से राष्ट्र की एकता,अखण्डता एवं विकास की दिशा में हिन्दी पत्रकारिता की भूमिका को कदापि नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।

हालांकि हिन्दी पत्रकारिता के 200 वर्षों के इतिहास में समय के साथ पत्रकारिता के मायने और उद्देश्य बदलते रहे हैं किन्तु उसके बावजूद सुखद स्थिति यह है कि हिन्दी पत्रकारिता के पाठकों या दर्शकों की रूचि में कोई कमी नहीं आई। यह अलग बात है कि अंग्रेजी मीडिया और उससे जुड़े कुछ पत्रकारों ने भले ही हिन्दी पत्रकारिता की उपेक्षा करते हुए सदैव उसकी प्रामाणिकता एवं विश्वसनीयता पर सवाल उठाने की कोशिशें की हैं किन्तु वास्तविकता यही है कि पिछले कुछ दशकों में हिन्दी पत्रकारिता ने अपनी ताकत का बखूबी अहसास कराया है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी उसकी विश्वसनीयता बढ़ी है। यह हिन्दी पत्रकारिता की बढ़ती ताकत का ही नतीजा है कि कुछ हिन्दी अखबारों ने अनेक संस्करणों के साथ प्रसार संख्या के मामले में कुछ अंग्रेजी अखबारों को भी पीछे छोड़ दिया है।

हिन्दी पत्रकारिता की शुरूआत 30 मई 1826 को कानपुर निवासी पं. युगुल किशोर शुक्ल द्वारा प्रथम हिन्दी समाचार पत्र 'उदन्त मार्तण्ड' के प्रकाशन के साथ हुई थी,जिसका अर्थ था 'समाचार सूर्य'। उस समय अंग्रेजी, फारसी और बांग्ला में कई समाचारपत्र निकल रहे थे किन्तु हिन्दी का पहला समाचारपत्र 'उदन्त मार्तण्ड' 30 मई 1826 को कलकत्ता से पहली बार प्रकाशित हुआ था,जो साप्ताहिक के रूप में आरंभ किया गया था। पहली बार उसकी केवल 500 प्रतियां ही छापी गई थी लेकिन चूंकि कलकत्ता में हिन्दी भाषियों की संख्या काफी कम थी और इसके पाठक कलकत्ता से बहुत दूर के भी होते थे,इसीलिए संसाधनों की कमी के कारण यह लंबे समय तक प्रकाशित नहीं हो पाया। 4 दिसम्बर 1826 से 'उदन्त मार्तण्ड' का प्रकाशन बंद कर दिया गया लेकिन इस समाचारपत्र के प्रकाशन के साथ ही हिन्दी पत्रकारिता की ऐसी नींव रखी जा चुकी थी कि उसके बाद से हिन्दी पत्रकारिता ने अनेक आयाम स्थापित किए हैं। 'उदन्त मार्तण्ड' के बाद अंग्रेजी शासनकाल में अनेक हिन्दी समाचारपत्र व पत्रिकाएं एक मिशन के रूप में निकलते गए किन्तु ब्रिटिश शासनकाल की ज्यादतियों के चलते उन्हें लंबे समय तक चलाते रहना बड़ा मुश्किल था, फिर भी कुछ पत्र-पत्रिकाओं ने सराहनीय सफर तय किया। अब परिस्थितियां बिल्कुल बदल चुकी हैं और हिन्दी पत्रकारिता भी मिशन न रहकर एक बड़ा व्यवसाय बन गई है किन्तु अच्छी बात यह है कि आज भी हिन्दी पाठक व दर्शक अपनी-अपनी पसंद के अखबारों व चैनलों के साथ पूरी शिद्दत से जुड़े हैं।

बहरहाल,घर बैठे-बैठे दुनिया की सैर कराने की बात हो या देश-विदेश की हर छोटी-बड़ी हलचल से लेकर तमाम ज्वलंत मुद्दों और हर प्रकार की नवीनतम जानकारियों को जुटाकर अपने पाठकों या दर्शकों के सामने प्रस्तुत करने की,व्यवसायीकरण के आरोपों या तमाम विरोधाभासों के बावजूद हिन्दी पत्रकारिता भी यह काम बखूबी कर रही है और आमजन के भरोसे पर खरा उतरते हुए हिन्दी पत्रकारिता आज आम जनजीवन का अभिन्न अंग बन चुकी है। अधिकांश हिन्दी समाचार पत्रों के अब ऑनलाइन संस्करण उपलब्ध हैं। विगत कुछ वर्षों में देश में बड़े-बड़े घोटालों का पर्दाफाश करके अनेक सफेदपोशों के चेहरों पर पड़े नकाब उतार फैंकने का श्रेय भी पत्रकारिता जगत को ही जाता है, जिसमें हिन्दी पत्रकारिता की भूमिका को भी किसी भी लिहाज से कमतर नहीं आंका जा सकता।

जहां तक राष्ट्रीय अखंडता में प्रेस की भूमिका और इसके दायित्वों का प्रश्न है तो प्रेस के कई प्रमुख दायित्व माने गए हैं,जिनमें कानून व्यवस्था की खामियों को प्रकाशित-प्रसारित करना, अपने प्रयासों से शासन को सुव्यवस्थित करना व लोक हितकारी बनाना,पथभ्रष्टों को सन्मार्ग पर लाना, भ्रष्ट तंत्र को चौकन्ना बनाना, असामाजिक तत्वों पर कड़ी नजर रखना,समाज के विभिन्न क्षेत्रों में पर्दे की ओट में होने वाले दुष्कृत्यों,अत्याचारों व अन्याय का जनहित में पर्दाफाश करना,समाज व मानवता के गुनाहगार चेहरों पर पड़े नकाब नोचकर जनता के सामने लाना, निजी स्वार्थों की पूर्ति के लिए धार्मिकता एवं राजनीति की आड़ लेने वालों के राज पर्दाफाश करना, समाज में स्वस्थ मानक स्थापित करना, लोक चेतना जागृत करना इत्यादि शामिल हैं। प्रेस की भूमिका पर टिप्पणी करते हुए महात्मा गांधी ने कहा था, ''प्रेस का प्रथम उद्देश्य जनता की इच्छाओं व विचारों को समझना और उन्हें सही ढ़ंग से व्यक्त करना है जबकि दूसरा उद्देश्य जनता में वांछनीय भावनाओं को जागृत करना और तीसरा उद्देश्य सार्वजनिक दोषों को निर्भयता पूर्वक प्रकट करना है।''

लोकतंत्र में प्रेस की भूमिका के बारे में पूर्व राष्ट्रपति डा. शंकर दयाल शर्मा ने कहा था कि प्रेस पर लोकतांत्रिक परम्पराओं की रक्षा करने और शांति व भाईचारा बढ़ाने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। राष्ट्रीय अखण्डता के संदर्भ में पत्रकारिता की भूमिका की बात करें तो लोकतंत्र के अन्य स्तंभों के मुकाबले प्रेस की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण है,इसका अनुमान इसी से लगाया जा सकता है कि विश्वभर में भारत की प्रतिष्ठा के जो तीन प्रमुख कारण माने गए हैं,वे हैं जागरूक मतदाता,स्वतंत्र न्यायपालिका व स्वतंत्र प्रेस। भारत में प्रेस को जनता की एक ऐसी 'संसद'की उपाधि दी गई है, जिसका कभी सत्रावसान नहीं होता और जो सदैव जनता के लिए ही कार्य करती है। इसे समाज में परिवर्तन लाने का अथवा उसे जागृत करने के लिए जन संचार का सशक्त माध्यम माना गया है। प्रेस को समाज की चिंतन प्रक्रिया का एक ऐसा अनिवार्य तत्व माना गया है, जो उसे दिशा व गति देने में सक्षम हो। इसे जनता की ऐसी आंख माना गया है, जो सभी पर अपनी पैनी और निष्पक्ष दृष्टि रखे। प्रेस को जनता की उंगली माना गया है, जो गलत कार्यों के विरोध में स्वतः ही उठ जाती है। प्रेस को समाज के प्रति पूर्ण समर्पण के रूप में देखा जाता है। इसे केवल एक पेशा न मानकर जनसेवा का सबसे बड़ा माध्यम माना गया है।

वर्तमान में जहां देशभर में नैतिक मूल्यों में बड़ी गिरावट आई है और राजनीतिज्ञों,विधायिका,कार्यपालिका तथा न्यायिक व्यवस्था पर से लोगों का विश्वास कम हो रहा है,वहीं हिन्दी पत्रकारिता भी इस नैतिक पतन का शिकार होने से नहीं बची है। फिर भी इतना संतोष तो किया ही जा सकता है कि इसने इसके बावजूद अधिकांश अवसरों पर सराहनीय भूमिका निभाई है। हालांकि आज के पूर्ण व्यावसायिकता के दौर में पत्रकारिता को अव्यावसायिक बनाए रखने की बात करना बेमानी होगा क्योंकि इस पेशे से जुड़े लोगों को भी अपने परिवार के पालन-पोषण के लिए इसे एक व्यवसाय के रूप में अपनाना अनिवार्य होता गया है लेकिन व्यावसायिकता के इस दौर में भी इसे एक उद्योग-धंधे के रूप में स्थापित करने के प्रयासों के चलते पत्रकारिता के मानदंडों को ताक पर रखने की प्रवृति से तो हर हाल में बचना ही चाहिए।

दुश्मनी जमकर करो लेकिन...

कृष्ण कुमार निर्माण
करनाल,हरियाणा

सैयद मोहम्मद बशीर जो बाद में बशीर बद्र के नाम से मशहूर हुए तो कह उठे कि...

उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दों,
न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए।।

और गत अठाईस मई को भोपाल में तमाम यादों,अनुभवों के संग शाम हो गई।क्योंकि बशीर ने जिंदगी के तमाम उतार चढ़ाव देखे,संघर्ष किए और दंगों को भी भुगता,न केवल भुगता बल्कि कहा कि...

लोग टूट जाते हैं
एक घर बनाने में,
तुम तरस नहीं खाते
बस्तियां जलाने में।।

और यकीन मानिए आज भी वैसा ही हो रहा है पर किसे फिक्र हैं क्योंकि जब इंसान बंट जाता है तब वह इंसान नहीं रहता बल्कि जहरीला सांप हो जाता है बस खोल ही इंसान का होता है? पन्द्रह फरवरी उन्नीस सौ तीस में जन्में बशीर ने पीएचडी तक शिक्षा प्राप्त की और मेरठ कालेज में लंबे समय तक प्रोफेसर रहे पर उन्नीस सौ सतासी में मेरठ छोड़ना पड़ा और भोपाल आकर बस गए और रचनाधर्मिता में ऐसे तल्लीन हुए कि उन्होंने गजल को मीर और गालिब के पारंपरिक ढर्रे से न केवल निकाला बल्कि वर्तमान दौर के शायरों के लिए नई ताबीर भी लिखी,तभी तो उन्हें पदम श्री और साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया क्योंकि बशीर की शाइरी का मिजाज आम आदमी की हालातों से गुजरता है कि...

कोई हाथ भी न मिलाएगा जो गले मिलोगे तपाक से,ये नए मिजाज का शहर है जरा फासले से मिला करो।

और यकीन मानिए ऐसा ही हो रहा है आजकल पूरी दुनिया में,,यही एक शाइर की खूबी होती है कि वो समय की नब्ज पके कर लिखता है और ऐसा लिखता है कि जब भी पढ़ो,वो नया लगता है। उनकी शाइरी में सादगी,तल्खी और मुहब्बत का जो संगम था,वो विरल है।उनकी शाइरी की एक खास बात यह भी रही कि बशीर साहब ने कठिन लफ्जों के जाल से मुक्त होकर आम बोलचाल की भाषा को उर्दू जुबान दी और शायद यही वजह है कि उनके कलाम हर खास-ओ-आम की जुबान पर आ जाते हैं कि...

आखिर कुछ तो मजबूरियाँ ही होंगी,वरना यों ही कोई बेवफा नहीं होता।

यह शेर न जाने कितने आयाम खोलता है।आम बात से लेकर महबूब तक और तमाम चीजों को खोल देता है।उनका एक शेर जो आज के हालातों पर भी खरा उतरता है कि...

जी बहुत चाहता है सच बोलें,
क्या करें होंसला नहीं होता।

है ना गजब कितनी सरलता से कितनी बड़ी बात कहने में सफल हो गए बशीर साहब। यही कमाल था बशीर बद्र जी का।बशीर के अवसान के बाद जो वर्तमान दौर है कि सोशल मीडिया का,डिजिटल दुनिया का,जिसमें आए दिन हजारों कवि/ शायर जन्म ले रहे हैं,उस दौर में यह बात हर शायर/कवि को अपने जेहन में बिठा लेनी चाहिए कि एक सच्चे रचनाकार का काम सिर्फ मुहब्बत की बातें करना नहीं होता बल्कि अपने समय की राजनीति और समाज के दोगलेपन पर सवाल उठाना भी होता है और अगर ऐसा नहीं कर रहे तो फिर शाइरी छोड़ दीजिए,कुछ और काम करिए। क्योंकि यह बशीर ही कहने की हिमाकत मर सकते हैं कि...

जीभ पर सुखी हुई गालियाँ अच्छी नहीं।
कुर्सियों पर बैठकर गालियाँ अच्छी नहीं।

और आज यही तो हो रहा है।एक और शेर देखिएगा कि...

दुश्मनी जमकर करो लेकिन यह गुंजाइश रहे।
जब कभी हम दोस्त हों जाएं तो शर्मिंदा न हों।।

बकौल बशीर बद्र एक शायर/कवि को सदा अपनी रीढ़ मजबूत रखनी चाहिए,उसे सत्ता के सामने झुकने की बजाय अपनी कलम की खुद्दारी को जिंदा रखना चाहिए।तभी तो बशीर यह कह पाए कि...

मुसाफिर के रास्ते बदलते रहे,
मगर हम तो अपनी डगर चलते रहे।।

इतना ही नहीं...

शौहरत की धूप आते ही साये सिमट गए।
हम ढलती शाम तक इसी दीवार के रहे।

बेशक बशीर साहब का फिल्मी सफर बहुत लंबा नहीं रहा क्योंकि बशीर अपनी शर्तों पर लिखने वाले शायर थे मगर फिर भी वॉलीवुड उनकी गजलियत का मुरीद रहा और जगजीत सिंह,पंकज उधास और गुलाम अली जैसे गजल गायकों ने उनकी गजलों को आवाज दी।आज बशीर नहीं रहे पर उनकी यह शाइरी सदियों तक गूंजती रहेगी कि...

सात संदूकों में भरकर दफ्न कर दो नफरतें।
आज इंसाँ को मुहब्बत की जरूरत बहुत है।।

अलविदा बशीर साहब।तुम शाइरी में हमेशा जिंदा रहोगे।

प्रकाशक: दैनिक घटती-घटना

शादी या सज़ा? आधुनिक भारत में बदलते रिश्तों की कड़वी हकीकत

घरेलू हिंसा का नया चेहरा: प्रतिष्ठित परिवार और टूटती बेटियाँ
एक विवाह,कई सवाल : क्या बेटियाँ सुरक्षित हैं अपने ही घरों में?

कृति आरके जैन
बड़वानी,मध्यप्रदेश

जब किसी युवती के जीवन में सपनों की रोशनी और आत्मनिर्भरता का विश्वास मौजूद हो, और वही जीवन शादी के कुछ ही महीनों बाद ससुराल की दीवारों के भीतर थम जाए, तो यह केवल एक परिवार की त्रासदी नहीं,बल्कि पूरे समाज की चेतना पर सवाल बन जाता है। नोएडा की त्विषा शर्मा की संदिग्ध मृत्यु ने उस चुप्पी को तोड़ दिया,जिसे हम लंबे समय से पारिवारिक मामला कहकर नजरअंदाज करते आए हैं। मैं फँस गई हूँ जैसे अंतिम संदेश किसी साधारण स्थिति नहीं,बल्कि भीतर घुटते जीवन की दर्दभरी पुकार हैं,जिन्हें समय रहते सुनने में समाज असफल रहा। यह घटना याद दिलाती है कि हिंसा हमेशा खुले रूप में नहीं होती, बल्कि कई बार वह बंद दरवाजों के भीतर सबसे खतरनाक और अदृश्य रूप में मौजूद रहती है।

विवाह नहीं,नियंत्रण का ढांचा बनती सोच

त्विषा की घटना केवल एक व्यक्तिगत दुख नहीं,बल्कि उस सामाजिक सोच का प्रतिबिंब है जो विवाह को बराबरी का रिश्ता नहीं, बल्कि नियंत्रण और अपेक्षाओं का ढांचा मानती है। शादी के बाद महिला से यह उम्मीद की जाती है कि वह अपने सपनों को पीछे छोड़ दे,अपने फैसलों को सीमित कर दे और अपने अस्तित्व को परिवार की इच्छाओं में ढाल ले। दहेज की मांग,ताने और समायोजन के नाम पर सहनशीलता की परीक्षा–ये सब मिलकर एक अदृश्य बंधन बनाते हैं जहाँ हिंसा को सामान्य माना जाता है। सबसे चिंताजनक पहलू यह है कि समय के साथ यह सब इतना सामान्य हो जाता है कि पीड़ित अपने दर्द को पहचानने और व्यक्त करने की शक्ति खोने लगती है।

सवालों के घेरे में सच्चाई : जांच की उलझती परतें

इस मामले को केवल आरोपों तक सीमित रखना इसकी गंभीरता को पूरी तरह समझने में चूक होगी,क्योंकि इसके इर्द-गिर्द खड़े सवाल इसे और जटिल बना देते हैं। पति और सास पर लगे आरोप,अंतिम दिनों की संदिग्ध परिस्थितियाँ, सीसीटीवी फुटेज में समय का अंतर और परिवार की चुप्पी–ये सब किसी सामान्य घटना की ओर संकेत नहीं करते। जब जांच की शुरुआत ही विरोधाभासों से भरी हो,तो न्याय तक पहुँचना और कठिन हो जाता है। यह स्थिति दिखाती है कि प्रभाव और संसाधनों की ताकत किस तरह सच्चाई को धुंधला कर सकती है, यदि व्यवस्था सतर्क न रहे।

परंपरा या पितृसत्ता? हिंसा की जड़ें

घरेलू हिंसा की जड़ें केवल व्यक्तियों में नहीं, बल्कि उस सामाजिक ढांचे में हैं जो पितृसत्ता को परंपरा और संस्कृति का नाम देकर स्वीकार कर लेता है। लंबे समय से यह धारणा है कि घर का नियंत्रण पुरुष के हाथ में होना चाहिए और स्त्री का कर्तव्य केवल सहना है। यही सोच हिंसा को रोकने के बजाय उसे सामान्य बना देती है। जब लड़की को बचपन से यह सिखाया जाता है कि रिश्ते निभाना सबसे बड़ा धर्म है, तो वह कई बार अपने खिलाफ हो रही हिंसा को भी रिश्ते की कीमत समझकर स्वीकार कर लेती है। यही स्वीकार्यता सबसे बड़ा खतरा है, क्योंकि यह अपराध को अदृश्य बना देती है।

कानून मजबूत,न्याय कमजोर : सिस्टम की हकीकत

मजबूत कानूनी प्रावधानों के बावजूद वास्तविकता यह है कि न्याय की गति अक्सर पीड़िताओं के दर्द और उम्मीदों से पीछे रह जाती है। घरेलू हिंसा और दहेज निषेध जैसे कानून कागजों पर सख्त हैं,लेकिन उनके प्रभावी क्रियान्वयन में संवेदनशीलता और त्वरित कार्रवाई की कमी दिखाई देती है। थानों में आज भी यह घर का मामला है जैसी सोच मौजूद है। अदालतों की लंबी और थकाऊ प्रक्रिया, साथ ही सामाजिक दबाव, पीड़ित परिवारों को मानसिक रूप से कमजोर कर देते हैं। देर से मिला न्याय सुरक्षा नहीं,केवल औपचारिक निर्णय बनकर रह जाता है, और इसी कारण कई मामले न्याय तक पहुँच ही नहीं पाते।

पीड़िता पर सवाल : समाज की सबसे बड़ी चूक

समाज की सबसे गहरी विडंबना उसकी उस प्रतिक्रिया में छिपी है, जो पीड़ा को समझने के बजाय पीड़िता के व्यवहार का मूल्यांकन करने लगती है। यहाँ प्रश्न यह नहीं होता कि उसने कितना सहा,बल्कि यह पूछा जाता है कि उसने विरोध क्यों नहीं किया। यही सोच पीड़िता को बार-बार चोट पहुँचाती है। त्विषा जैसे मामलों में चर्चा अक्सर उसकी जीवनशैली या रिश्तों के इर्द-गिर्द घूमने लगती है,जबकि मूल सवाल यह होना चाहिए कि उसे सुरक्षित और सम्मानजनक वातावरण क्यों नहीं मिला। जब तक हम पीड़िता को संदेह की नजर से देखना बंद नहीं करेंगे,तब तक न्याय केवल एक औपचारिक प्रक्रिया बनकर ही रह जाएगा।

बदलाव की अनिवार्यता : सोच और व्यवस्था का पुनर्गठन

आज जरूरत केवल कानूनों की नहीं, बल्कि व्यवस्था और सामाजिक सोच के गहरे एवं निर्णायक पुनर्गठन की है। हर थाने में प्रशिक्षित महिला सहायता इकाइयों की स्थापना,त्वरित फोरेंसिक जांच,डिजिटल साक्ष्य संरक्षण और समयबद्ध न्याय प्रक्रिया को अनिवार्य करना अब आवश्यकता है। स्कूलों और विश्वविद्यालयों में संबंधों की समझ,सहमति, सम्मान और मानसिक स्वास्थ्य को शिक्षा का हिस्सा बनाना जरूरी है। समाज को यह स्वीकार करना होगा कि घरेलू हिंसा कोई निजी विवाद नहीं,बल्कि गंभीर आपराधिक अपराध है। जब तक इसे सामाजिक शर्म के बजाय कानूनी अपराध के रूप में नहीं देखा जाएगा,तब तक बदलाव अधूरा ही रहेगा।

त्विषा की कहानी किसी खबर का अंत नहीं, बल्कि उस कठोर सच्चाई की शुरुआत है जिसे समाज बार-बार अनदेखा करता आया है। यह घटना सवाल उठाती है कि क्या हम ऐसा समाज बना पाए हैं जहाँ बेटी का जन्म उत्सव हो, लेकिन उसका जीवन सुरक्षित न हो? अब समय केवल नारों का नहीं, उन्हें वास्तविकता में बदलने का है : बेटी बचाओ से आगे बढ़कर बेटी को अधिकार,सुरक्षा और सम्मान दो को सच में अपनाना होगा। यदि हम आज भी मौन रहे,तो ऐसी घटनाएँ अपवाद नहीं, बल्कि एक दुखद सामान्यता बन जाएँगी,और यही किसी सभ्य समाज की सबसे बड़ी विफलता होगी।

प्रकाशक: दैनिक घटती-घटना

सरकारी जमीनों पर कब्जा : जिम्मेदार अधिकारियों पर हो कड़ी कार्यवाही

-डॉ. शैलेश शुक्ला-

भारत में सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जे का प्रश्न केवल भूमि विवाद या प्रशासनिक लापरवाही का विषय नहीं रह गया है,बल्कि यह शासन व्यवस्था,भ्रष्टाचार,राजनीतिक संरक्षण और प्रशासनिक जवाबदेही से जुड़ा एक गंभीर राष्ट्रीय संकट बन चुका है। देश के लगभग प्रत्येक राज्य में समय-समय पर सरकारी भूमि,ग्राम समाज की जमीन,वन भूमि,तालाब,सार्वजनिक उपयोग की भूमि और विकास परियोजनाओं के लिए सुरक्षित क्षेत्रों पर अवैध कब्जों की खबरें सामने आती रहती हैं। सबसे चिंताजनक तथ्य यह है कि ऐसे अधिकांश कब्जे अचानक नहीं हो जाते। वर्षों तक निर्माण कार्य चलता है, सीमांकन बदलते हैं,दस्तावेज तैयार होते हैं, बिजली-पानी के कनेक्शन दिए जाते हैं, सड़कें बन जाती हैं और पूरा तंत्र सब कुछ देखता रहता है। ऐसे में यह मान लेना कठिन है कि सरकारी भूमि पर बड़े पैमाने पर होने वाले कब्जों से प्रशासन पूरी तरह अनजान रहता है। यही कारण है कि अब यह प्रश्न अधिक गंभीरता से उठने लगा है कि केवल अवैध कब्जाधारियों के विरुद्ध ही नहीं,बल्कि उन अधिकारियों और कर्मचारियों के विरुद्ध भी कठोर कार्रवाई होनी चाहिए जिनकी लापरवाही,मिलीभगत या भ्रष्ट आचरण के कारण सरकारी संपत्तियाँ धीरे-धीरे निजी नियंत्रण में चली जाती हैं। सरकारी भूमि किसी सरकार, विभाग या अधिकारी की निजी संपत्ति नहीं होती। वह जनता की सामूहिक संपत्ति होती है। उस भूमि का उद्देश्य सार्वजनिक हित,विकास कार्य,पर्यावरण संरक्षण,शिक्षा, स्वास्थ्य,परिवहन,जल संरक्षण और भविष्य की आवश्यकताओं के लिए सुरक्षित रहना होता है। जब ऐसी भूमि पर अवैध कब्जा हो जाता है,तो सबसे बड़ा नुकसान आम जनता को होता है। कई शहरों में तालाबों और जल निकासी क्षेत्रों पर कब्जे के कारण हर वर्ष जलभराव और बाढ़ जैसी स्थितियाँ उत्पन्न होती हैं। पार्क,खेल मैदान और सार्वजनिक उपयोग की जमीनें धीरे-धीरे गायब हो जाती हैं। ग्राम समाज की जमीनों पर अवैध निर्माण होने से ग्रामीणों के सामुदायिक अधिकार प्रभावित होते हैं। वन भूमि पर अतिक्रमण पर्यावरणीय संकट को बढ़ाता है। इस प्रकार सरकारी भूमि पर कब्जा केवल भूमि हड़पने का मामला नहीं, बल्कि सार्वजनिक अधिकारों और भविष्य की पीढ़ियों के हितों पर सीधा हमला है। सबसे गंभीर चिंता यह है कि अनेक मामलों में अवैध कब्जे वर्षों तक जारी रहते हैं और प्रशासनिक मशीनरी निष्क्रिय बनी रहती है। यदि किसी छोटे गरीब व्यक्ति द्वारा मामूली अतिक्रमण किया जाए, तो प्रशासन अक्सर तुरंत सक्रिय हो जाता है, लेकिन जब बड़े भू-माफिया,प्रभावशाली लोग या राजनीतिक संरक्षण प्राप्त समूह सरकारी जमीनों पर कब्जा करते हैं, तब कार्रवाई वर्षों तक लंबित रहती है। यही दोहरा व्यवहार जनता के भीतर व्यवस्था के प्रति अविश्वास पैदा करता है। लोगों को यह महसूस होने लगता है कि कानून केवल कमजोर लोगों पर लागू होता है,जबकि प्रभावशाली लोगों के लिए अलग व्यवस्था चलती है। लोकतंत्र में यह स्थिति अत्यंत खतरनाक होती है,क्योंकि इससे शासन व्यवस्था की नैतिक विश्वसनीयता कमजोर होती है। भारत के अनेक राज्यों में समय-समय पर सरकारी भूमि पर कब्जों को लेकर बड़े अभियान चलाए गए हैं। बुलडोजर कार्रवाई,भूमि मुक्त अभियान और राजस्व अभिलेखों की डिजिटल जाँच जैसी पहलें कई स्थानों पर दिखाई दी हैं। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि यदि सरकारी भूमि वर्षों तक कब्जे में रही,तो उसके लिए जिम्मेदार कौन था। क्या स्थानीय राजस्व अधिकारी, नगर निकाय,विकास प्राधिकरण, पुलिस प्रशासन और संबंधित विभागों को इसकी जानकारी नहीं थी? यदि जानकारी थी, तो कार्रवाई क्यों नहीं हुई? यदि जानकारी नहीं थी,तो यह प्रशासनिक विफलता है।

सूचना

समाचार पत्र में छपे समाचार एवं लेखों पर सम्पादक की सहमति आवश्यक नहीं है। हमारा ध्येय तथ्यों के आधार पर सटिक खबरें प्रकाशित करना है न कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना। सभी विवादों का निपटारा अम्बिकापुर न्यायालय के अधीन होगा।

-सम्पादक

विधायक बनाम नायब तहसीलदार विवाद गहराया...गिरफ्तारी देने निकले रामकुमार टोप्पो को समर्थकों ने बीच रास्ते रोका

सरगुजा संभाग में प्रशासनिक कामकाज ठप्प,कलमबंद हड़ताल पर अधिकारी-कर्मचारी,विधायक बोले...जांच में करूंगा पूरा सहयोग

-संवाददाता-
अम्बिकापुर/सीतापुर,29 मई 2026 (घटती-घटना)।
छत्तीसगढ़ के सरगुजा संभाग में सीतापुर विधायक रामकुमार टोप्पो और नायब तहसीलदार तुषार मानिकपुरी के बीच उपजा विवाद अब बड़े राजनीतिक और प्रशासनिक संकट का रूप लेता जा रहा है। विधायक और उनके समर्थकों पर नायब तहसीलदार से कथित मारपीट और दुर्व्यवहार का मामला दर्ज होने के बाद शुक्रवार को पूरा घटनाक्रम हाई-वोल्टेज ड्रामे में बदल गया। एक ओर प्रशासनिक अधिकारियों और कर्मचारियों ने गिरफ्तारी की मांग को लेकर कलमबंद हड़ताल कर दी, वहीं दूसरी ओर विधायक जब खुद गिरफ्तारी देने अंबिकापुर के लिए निकले तो समर्थकों ने बीच रास्ते में उनका काफिला रोक दिया और वापस लौटा दिया।

सड़क पर लेट गए समर्थक नहीं होने दी गिरफ्तारी

शुक्रवार दोपहर विधायक रामकुमार टोप्पो अपने कुछ निजी सहयोगियों के साथ सीतापुर से अंबिकापुर स्थित आईजी कार्यालय के लिए रवाना हुए थे। उन्होंने पहले ही सार्वजनिक रूप से कहा था कि वे कानून से भागेंगे नहीं और स्वयं गिरफ्तारी देंगे। इसके साथ ही विधायक ने अपने समर्थकों से शांति बनाए रखने, किसी प्रकार का प्रदर्शन नहीं करने और प्रशासनिक व्यवस्था में बाधा नहीं डालने की अपील भी की थी। लेकिन उनकी अपील का असर नहीं हुआ। सीतापुर से लगभग 15 किलोमीटर दूर मंगारी के पास पहले से मौजूद बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ताओं और ग्रामीणों ने विधायक के काफिले को रोक लिया। कई समर्थक गाड़ियों के सामने धरने पर बैठ गए,जबकि कुछ लोग सड़क पर लेट गए। कार्यकर्ताओं ने मानव श्रृंखला बनाकर काफिले को आगे बढ़ने से रोक दिया। समर्थक लगातार नारेबाजी करते रहे और कहते रहे कि वे अपने नेता को जेल नहीं जाने देंगे। कई कार्यकर्ता भावुक होकर रोते-बिलखते नजर आए।

समर्थकों की जिद के आगे झुके विधायक

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार विधायक टोप्पो ने काफी देर तक कार्यकर्ताओं को समझाने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि वे कानून और न्यायपालिका का सम्मान करते हैं तथा जांच में पूरा सहयोग करेंगे। लेकिन समर्थकों ने उनकी एक नहीं सुनी। मौके पर मौजूद लोगों का कहना था कि कार्यकर्ताओं ने विधायक का हाथ पकड़कर उन्हें वाहन से नीचे उतार लिया और वापस लौटने की मांग पर अड़ गए। आखिरकार समर्थकों के भारी दबाव के आगे विधायक को अपना अंबिकापुर दौरा स्थगित करना पड़ा और वे वापस सीतापुर लौट गए। इस पूरे घटनाक्रम ने सरगुजा की राजनीति में नया मोड़ ला दिया है।

विधायक बोले...हम पूरी तरह न्यायपालिका के साथ : विधायक रामकुमार टोप्पो ने पूरे मामले में कहा कि वे पूरी तरह न्यायपालिका और शासन के साथ हैं तथा जांच में पूरा सहयोग करेंगे। उन्होंने कहा,'मैं अपने दल और वरिष्ठ अधिकारियों को सूचना देने के बाद जहां उचित होगा, वहां गिरफ्तारी दूंगा।'विधायक ने सीतापुर और सरगुजा संभाग की जनता द्वारा मिल रहे समर्थन के लिए आभार व्यक्त किया और सभी से शांति बनाए रखने की अपील की।

सरगुजा में प्रशासनिक कामकाज ठप्प...कलमबंद हड़ताल

इधर विधायक और उनके समर्थकों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर शुक्रवार को छत्तीसगढ़ कनिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी सेवा संघ से जुड़े अधिकारी-कर्मचारी कलमबंद हड़ताल पर रहे। सरगुजा संभाग में राजस्व और प्रशासनिक कामकाज लगभग पूरी तरह प्रभावित रहा। प्रदेशभर के तहसीलदार और नायब तहसीलदार भी विरोध में हड़ताल पर रहे। राजमोहिनी देवी भवन में संघ से जुड़े अधिकारियों और कर्मचारियों ने सभा आयोजित की, जिसके बाद रैली निकालकर कलेक्ट्रेट पहुंचे और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। संघ ने चेतावनी दी है कि यदि आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होती है तो आगे अनिश्चितकालीन हड़ताल की जाएगी।

क्या है पूरा मामला

दरअसल विवाद की शुरुआत 27 मई को राजापुर उप तहसील कार्यालय में हुई घटना से हुई थी। विधायक रामकुमार टोप्पो की बड़ी बहन सीमा धनकी पैरोल से संबंधित दस्तावेज पर हस्ताक्षर कराने उप तहसील कार्यालय पहुंची थीं। आरोप है कि वहां पदस्थ नायब तहसीलदार तुषार मानिकपुरी ने उनकी फाइल फेंक दी और उनके साथ बदसलूकी करते हुए कार्यालय से बाहर निकलने के लिए कहा। इसके बाद मामला बढ़ गया। नायब तहसीलदार का आरोप है कि विधायक द्वारा उन्हें राजापुर चौक पर बुलाया गया,जहां विधायक समर्थकों ने पहले उनकी पिटाई की और बाद में विधायक ने भी मारपीट की। इस मामले में सीतापुर एसडीएम फागेश सिन्हा ने भी कहा था कि उनके सामने विधायक और समर्थकों द्वारा मारपीट की गई। घटना के बाद विधायक रामकुमार टोप्पो और उनके 10 समर्थकों के खिलाफ कोतवाली अंबिकापुर में एफआईआर दर्ज की गई। वहीं विधायक की बहन की शिकायत पर नायब तहसीलदार तुषार मानिकपुरी के खिलाफ भी सीतापुर थाने में अपराध दर्ज किया गया है।

विधायक बनाम नायब तहसीलदार विवाद गहराया

गिरफ्तारी देने निकले रामकुमार टोप्पो को समर्थकों ने बीच रास्ते रोका

प्रशासनिक अधिकारियों के व्यवहार की भी हो जांच : विश्वविजय तोमर

छत्तीसगढ़ युवा आयोग के अध्यक्ष विश्वविजय सिंह तोमर ने मामले में कांग्रेस नेताओं की आलोचना करते हुए कहा कि उन्हें इस विषय पर टिप्पणी करने का नैतिक अधिकार नहीं है। उन्होंने कहा कि विधायक रामकुमार टोप्पो के खिलाफ आरोप लगते ही एफआईआर दर्ज कर ली गई, जो सरकार की पारदर्शिता को दर्शाता है। साथ ही विधायक स्वयं जांच में सहयोग की बात कर रहे हैं। तोमर ने मांग की कि विधायक की बहन के साथ कथित बदसलूकी और प्रशासनिक अधिकारियों के व्यवहार की भी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। उन्होंने कांग्रेस नेताओं टी. एस. सिंहदेव और अमरजीत भगत पर पलटवार करते हुए आरोप लगाया कि पूर्व में भी कई घटनाओं में कार्रवाई नहीं हुई थी। तोमर ने कहा कि कलेक्टर स्तर की समीक्षा बैठकों में ऐसे राजस्व, प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों के व्यवहार की समीक्षा होनी चाहिए, जिनका जनता से सीधा संपर्क रहता है। उन्होंने कहा कि अधिकारियों का व्यवहार जवाबदेह और संवेदनशील होना चाहिए।

प्रदेश की राजनीति में बना चर्चा का विषय...

राजस्व अधिकारियों की हड़ताल,विधायक पर एफआईआर,गिरफ्तारी की तैयारी और फिर समर्थकों द्वारा रास्ता रोककर उन्हें वापस लौटाने की घटना अब प्रदेशभर में चर्चा का विषय बन गई है। एक ओर प्रशासनिक अमला मामले में सख्त कार्रवाई की मांग कर रहा है,वहीं भाजपा कार्यकर्ता इसे राजनीतिक प्रतिशोध और जनप्रतिनिधि का अपमान बता रहे हैं। पूरे घटनाक्रम ने सरगुजा संभाग की राजनीति और प्रशासनिक माहौल को गरमा दिया है।

एक्टिवा चोरी का खुलासा आदतन चोर गिरफ्तार

पुलिस ने चोरी गई स्कूटी बरामद की,आरोपी पर पहले से दर्ज हैं 7 आपराधिक मामले

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,29 मई 2026 (घटती-घटना)।
स्कूटी चोरी के मामले में थाना कोतवाली पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए एक आदतन चोर को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के कब्जे से चोरी गई एक्टिवा स्कूटी भी बरामद कर ली गई है। पुलिस ने आरोपी को न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया है। सरगुजा डीआईजी एवं एसएसपी राजेश अग्रवाल के निर्देशन में जिले भर में अपराधियों की धरपकड़ के लिए लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इसी अभियान के तहत थाना कोतवाली पुलिस को यह सफलता मिली।

मकान के बाहर से चोरी हुई थी स्कूटी

पुलिस के अनुसार प्रार्थिया प्रीति शुक्ला निवासी मिशन चौक अंबिकापुर ने 29 मई 2026 को थाना कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 27 मई की शाम लगभग 7 बजे उन्होंने अपनी एक्टिवा 3जी स्कूटी क्रमांक CG 15 CY 9930 को चोपड़ापारा स्थित आशियाना कंस्ट्रक्शन के सामने गली में खड़ी किया था। रात लगभग 10 बजे तक स्कूटी वहीं खड़ी थी, लेकिन सुबह उठकर देखने पर वाहन गायब मिला। आसपास खोजबीन करने के बावजूद स्कूटी का कोई पता नहीं चला, जिसके बाद अज्ञात चोर के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया।

मुखबिर की सूचना पर आरोपी धराया

मामला दर्ज होने के बाद थाना कोतवाली पुलिस लगातार आरोपी की तलाश कर रही थी। इसी दौरान पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि रामेश्वर उर्फ अत्ता दास नामक युवक गुदरी बाजार चौक के पास चोरी की स्कूटी बेचने के लिए ग्राहक तलाश रहा है। सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर घेराबंदी की और आरोपी को हिरासत में ले लिया। पूछताछ में आरोपी ने चोरी करना स्वीकार कर लिया। इसके बाद आरोपी की निशानदेही पर पुलिस ने रूनझून तालाब के पास से चोरी गई एक्टिवा स्कूटी बरामद कर जब्त कर ली।

आरोपी पर पहले से दर्ज हैं 7 मामले

गिरफ्तार आरोपी की पहचान रामेश्वर दास उर्फ अत्ता, पिता सखा दास,उम्र 26 वर्ष, निवासी हर्राटिकरा चाटापारा थाना जयनगर जिला सूरजपुर के रूप में हुई है। पुलिस के मुताबिक आरोपी आदतन अपराधी है और उसके खिलाफ थाना कोतवाली अंबिकापुर में पहले से सात आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं। पर्याप्त साक्ष्य मिलने पर आरोपी को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया,जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया।

इन पुलिसकर्मियों की रही अहम भूमिका

पूरे मामले के खुलासे में थाना प्रभारी निरीक्षक शशिकांत सिन्हा,उपनिरीक्षक सीपी तिवारी,प्रधान आरक्षक राजेश चतुर्वेदी,सियाराम मरावी,आरक्षक अमित विश्वकर्मा,विवेक राय तथा थाना मणिपुर से आरक्षक उमाशंकर साहू की भूमिका महत्वपूर्ण रही।

लगातार बढ़ रही वाहन चोरी की घटनाएं

अम्बिकापुर शहर में बीते कुछ समय से दोपहिया वाहन चोरी की घटनाओं में वृद्धि देखी जा रही है। ऐसे में पुलिस की यह कार्रवाई आम लोगों के लिए राहत मानी जा रही है। पुलिस ने नागरिकों से भी अपील की है कि वाहन खड़ा करते समय सुरक्षा उपायों का विशेष ध्यान रखें और संदिग्ध गतिविधियों की तत्काल सूचना पुलिस को दें।

महिला सम्मान के मुद्दे पर भाजपा महिला मोर्चा का प्रदर्शन

कलेक्टर और एसपी को सौंपा ज्ञापन,नायब तहसीलदार की गिरफ्तारी व एस.टी. एक्ट के तहत कार्रवाई की मांग

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,29 मई 2026 (घटती-घटना)।
महिला सम्मान और सुरक्षा के मुद्दे को लेकर भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा सरगुजा ने सोमवार को जोरदार प्रदर्शन करते हुए कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा। महिला मोर्चा ने नायब तहसीलदार एवं कार्यपालिक मजिस्ट्रेट तुषार मानिक पर महिला के साथ अभद्र व्यवहार,जातिसूचक गाली-गलौज,अश्लील इशारे और धक्का-मुक्की करने के गंभीर आरोप लगाते हुए तत्काल गिरफ्तारी और एस.टी. एक्ट के तहत कठोर कार्रवाई की मांग की। यह प्रदर्शन भाजपा जिलाध्यक्ष भारत सिंह सिसोदिया, महापौर मंजूषा भगत,जिला पंचायत अध्यक्ष निरूपा सिंह, महिला मोर्चा प्रदेश महामंत्री फूलेश्वरी सिंह,जिला महामंत्री अरुणा सिंह तथा महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष शुभांगी बिहाड़े की उपस्थिति में किया गया।

शासकीय कार्य से पहुंची महिला के साथ अभद्रता का आरोप

महिला मोर्चा द्वारा प्रशासन को सौंपे गए ज्ञापन में बताया गया कि ग्राम कोटछाल, जनपद पंचायत मैनपाट निवासी श्रीमती सीमा धनकी अपने शासकीय कार्य से उप तहसील राजापुर कार्यालय पहुंची थीं। आरोप है कि इसी दौरान नायब तहसीलदार तुषार मानिक ने उनके साथ अमर्यादित व्यवहार किया। ज्ञापन के अनुसार महिला के साथ जातिगत टिप्पणी, अशोभनीय इशारे और धक्का-मुक्की जैसी घटनाएं हुईं, जिससे न केवल महिला की गरिमा को ठेस पहुंची बल्कि शासकीय पद की मर्यादा भी तार-तार हुई। महिला मोर्चा ने इसे महिला सम्मान और आदिवासी समाज के स्वाभिमान से जुड़ा गंभीर मामला बताते हुए प्रशासन से सख्त कदम उठाने की मांग की है।

'एफआईआर के बाद भी कार्रवाई नहीं' – महिला मोर्चा

भाजपा महिला मोर्चा ने आरोप लगाया कि थाना सीतापुर में एफआईआर दर्ज होने के बावजूद अब तक आरोपी अधिकारी पर एस.टी. एक्ट नहीं लगाया गया है और न ही उसकी गिरफ्तारी की गई है। महिला मोर्चा नेताओं ने कहा कि यदि आम व्यक्ति पर ऐसा आरोप होता तो तत्काल गिरफ्तारी हो जाती, लेकिन एक अधिकारी होने के कारण मामले में ढिलाई बरती जा रही है। इसे लेकर महिलाओं में भारी आक्रोश व्याप्त है।

तत्काल निलंबन और गिरफ्तारी की मांग

महिला मोर्चा ने प्रशासन से मांग की कि...
- आरोपी अधिकारी तुषार मानिक को तत्काल निलंबित किया जाएं...
- एस.टी. एक्ट सहित कठोर धाराएं जोड़ी जाएं...
- आरोपी की अविलंब गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएं...
- पीड़ित महिला को न्याय और सुरक्षा प्रदान की जाएं...

महिला मोर्चा ने चेतावनी दी कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन को और उग्र किया जाएगा तथा मामले को उच्च स्तर तक उठाया जाएगा।

बड़ी संख्या में मौजूद रहीं महिला कार्यकर्ता

प्रदर्शन और ज्ञापन सौंपने के दौरान भाजपा महिला मोर्चा की पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता बड़ी संख्या में उपस्थित रहीं। इनमें प्रमुख रूप से गुंजन सिंह देव, प्रियंका चौबे,नीलू गुप्ता,सरिता जायसवाल,अर्चना सिंह, बुधमेत कुजूर,सरस्वती यादव,संतोषी पावले,हीरमेन राजवाड़े,रूपा गुप्ता,बबली महंत,कमलेश्वरी पैकरा,ममता तिवारी, श्वेता गुप्ता,किरण साहू,सोनू तिग्गा और संगीता कंसारी सहित अन्य महिलाएं शामिल थीं।

प्रशासन की कार्रवाई पर टिकी नजरें

अब इस पूरे मामले में प्रशासन और पुलिस की अगली कार्रवाई पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। महिला संगठनों का कहना है कि यदि समय रहते निष्पक्ष कार्रवाई नहीं हुई तो यह मामला व्यापक जनआंदोलन का रूप ले सकता है।

एनएच-343 पर दर्दनाक हादसा...अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार गंभीर,प्राथमिक उपचार के बाद अंबिकापुर रेफर

-संवाददाता-
राजपुर,29 मई 2026 (घटती-घटना)।
बलरामपुर जिले के राजपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत निर्माणाधीन एनएच-343 पर शुक्रवार दोपहर एक सड़क हादसे में बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसा ग्राम हरितिमा गेट के पास हुआ, जहां उड़ती धूल के कारण दृश्यता प्रभावित होने से अज्ञात वाहन ने बाइक को टक्कर मार दी। प्राप्त जानकारी के अनुसार धनराज रवि पिता शरीफा रवि निवासी ग्राम शिवपुर, राजपुर से गैस सिलेंडर लेकर वापस अपने गांव लौट रहा था। इसी दौरान हरितिमा गेट के पास तेज रफ्तार अज्ञात वाहन की चपेट में आने से वह गंभीर रूप से घायल हो गया।

राहगीरों ने पहुंचाया अस्पताल : हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया। आसपास मौजूद लोगों और राहगीरों ने मानवता दिखाते हुए घायल युवक को तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र राजपुर पहुंचाया। चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद युवक की हालत गंभीर देखते हुए बेहतर इलाज के लिए जिला अस्पताल अंबिकापुर रेफर कर दिया।

उड़ती धूल बनी हादसे की वजह : स्थानीय लोगों का कहना है कि निर्माणाधीन एनएच-343 पर इन दिनों भारी वाहनों की आवाजाही और सड़क निर्माण कार्य के कारण लगातार धूल उड़ रही है। धूल के गुबार से सड़क पर चलने वाले वाहन चालकों को सामने का दृश्य स्पष्ट दिखाई नहीं देता, जिससे दुर्घटनाओं का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि सड़क निर्माण एजेंसी द्वारा नियमित पानी का छिड़काव नहीं कराया जा रहा है, जिसके कारण राहगीरों और वाहन चालकों को भारी परेशानी झेलनी पड़ रही है।

अज्ञात वाहन की तलाश में जुटी पुलिस : घटना की सूचना मिलने के बाद राजपुर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस अज्ञात वाहन की पहचान और चालक की तलाश में जुटी हुई है।

स्थानीय लोगों ने प्रशासन से निर्माणाधीन सड़क पर सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने, नियमित पानी का छिड़काव कराने और यातायात नियंत्रण के उपाय करने की मांग की है ताकि भविष्य में ऐसे हादसों पर रोक लगाई जा सके।

खाकी पर दाग : साथी आरक्षक की मौत के 126 दिन बाद भी सूरजपुर पुलिस के हाथ खाली

जांच अधिकारी पर आरोपी को बचाने का आरोप,परिजनों ने दी उग्र आंदोलन की चेतावनी

-संवाददाता-
सूरजपुर,29 मई 2026 (घटती-घटना)।

कर्तव्य निभाकर घर लौट रहे एक आरक्षक की दर्दनाक मौत को 126 दिन बीत चुके हैं, लेकिन सूरजपुर पुलिस अब तक न तो घटनाकारी वाहन का स्पष्ट खुलासा कर पाई है और न ही आरोपियों पर ठोस कार्रवाई हो सकी है। इस मामले ने पुलिस विभाग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब खुद खाकी पहनने वाले एक जवान को न्याय नहीं मिल पा रहा,तो आम जनता की सुरक्षा और न्याय का दावा कितना मजबूत है? आरक्षक अभय कुमार पाण्डेय की 2 फरवरी की शाम सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी। बताया जाता है कि वह ड्यूटी पूरी कर घर लौट रहे थे, तभी तेज रफ्तार वाहन ने उन्हें अपनी चपेट में ले लिया। हादसा इतना भयावह था कि मौके पर ही उनकी मौत हो गई। लेकिन घटना के चार महीने बाद भी मामले की जांच अधूरी है और परिवार न्याय के लिए दर-दर भटकने को मजबूर है।

'हाईटेक पुलिस' की जांच पर उठ सवाल

मृतक आरक्षक के परिजनों का आरोप है कि खुद को आधुनिक और हाईटेक बताने वाली सूरजपुर पुलिस अब तक उस पिकअप वाहन और चालक तक नहीं पहुंच पाई,जिसने उनके बेटे की जान ली। परिजनों का कहना है कि घटना के तुरंत बाद प्रत्यक्षदर्शियों ने पुलिस को पूरी जानकारी दे दी थी,लेकिन पुलिस ने उस दिशा में गंभीरता से काम नहीं किया। परिवार का आरोप है कि हादसे में शामिल

वाहन उत्तरप्रदेश नंबर की पिकअप थी और शुरुआती दौर में पुलिस ने वाहन और चालक दोनों को पकड़ भी लिया था,लेकिन बाद में छोड़ दिया गया। अब महीनों बाद उसी चालक को पकड़कर केवल मामूली धाराओं में कार्रवाई कर थाने से ही जमानत दे दी गई। परिजनों ने जांच अधिकारी सुशील तिवारी पर सीधे आरोप लगाते हुए कहा है कि उन्होंने मामले को कमजोर करने और आरोपी को बचाने का प्रयास किया। परिवार का कहना है कि यदि समय रहते निष्पक्ष जांच होती तो अब तक दोषियों को सलाखों के पीछे भेजा जा चुका होता।

प्रत्यक्षदर्शी के बयान तक दर्ज नहीं

मामले में सबसे चौंकाने वाली बात यह सामने आई है कि घटना के प्रत्यक्षदर्शी का बयान तक अब तक विधिवत दर्ज नहीं किया गया। परिजनों का आरोप है कि मुख्य गवाह ने थाना प्रभारी को फोन पर घटना की पूरी जानकारी दी थी, लेकिन पुलिस ने उसे गंभीरता से नहीं लिया। इसी वजह से अब पूरे मामले में जांच की निष्पक्षता पर सवाल उठ रहे हैं। परिवार का कहना है कि मामले को जानबूझकर कमजोर किया जा रहा है ताकि आरोपी आसानी से बच सके।

सीसीटीवी और तकनीक पर भी उठ सवाल

परिजनों और स्थानीय लोगों ने शहर में लगे सीसीटीवी कैमरों और पुलिस की तकनीकी जांच पर भी सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि जब पूरे शहर में निगरानी कैमरे लगे हैं, तो आखिर घटनाकारी वाहन कैसे गायब हो गया? लोगों का कहना है कि यदि यही घटना किसी रसूखदार व्यक्ति, बड़े नेता या वरिष्ठ अधिकारी के साथ हुई होती, तो क्या पुलिस इतनी सुस्त रहती?

कार्रवाई नहीं हुई तो होगा बड़ा आंदोलन

अब मृतक आरक्षक के परिजनों और स्थानीय नागरिकों ने साफ चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई और निष्पक्ष जांच शुरू नहीं की गई, तो वे उग्र आंदोलन करने को मजबूर होंगे।

न्याय की आस में टूटता 'पुलिस परिवार'

इस घटना ने केवल एक परिवार नहीं,बल्कि पूरे पुलिस परिवार को झकझोर कर रख दिया है। घर में बूढ़े मां-बाप,पत्नी और मासूम बच्चे आज भी इंसाफ का इंतजार कर रहे हैं। परिवार का रो-रोकर बुरा हाल है।

मृतक के पिता का कहना है कि उनका बेटा पूरी जिंदगी दूसरों की सुरक्षा करता रहा, लेकिन आज उसके अपने ही विभाग ने उसे भुला दिया। उनका सवाल है...

अगर एक पुलिसकर्मी के हत्यारे को पुलिस नहीं पकड़ सकती,तो आम जनता को न्याय कैसे मिलेगा?

यह सवाल अब केवल एक परिवार का नहीं,बल्कि पूरे सिस्टम पर खड़ा होता दिख रहा है।

परिजनों ने मांग की है कि...

- मामले में सख्त धाराएं जोड़ी जाएं...
- आरोपी चालक की तत्काल गिरफ्तारी हों...
- जांच अधिकारी पर विभागीय कार्रवाई की जाए
- जांच किसी निष्पक्ष और सक्षम अधिकारी को सौंपी जाएं...

लोगों का कहना है कि यह मामला अब केवल एक सड़क दुर्घटना नहीं रह गया है,बल्कि यह खाकी के भीतर न्याय और संवेदनशीलता की असली परीक्षा बन चुका है।

सवाल जो जवाब मांग रहे हैं....

- क्या पुलिस अपने ही साथी को न्याय दिलाने में असफल हो गई है?
- आखिर 126 दिन बाद भी आरोपी खुलेआम कैसे घूम रहा है?
- क्या जांच को जानबूझकर कमजोर किया गया?
- क्या खाकी के भीतर भी अब संवेदनाएं फाइलों में दफन हो चुकी हैं?

इन सवालों के जवाब अब केवल अभय पाण्डेय का परिवार ही नहीं,बल्कि पूरा जिला जानना चाहता है।

सूरजपुर में अपराधियों पर न्यायालय का सख्त प्रहार 17 हत्या मामलों में 29 दोषियों को कठोर सजा

नए कानून के बाद न्याय व्यवस्था हुई और सख्त

-संवाददाता-
सूरजपुर,29 मई 2026 (घटती-घटना)।

सूरजपुर जिले में हत्या जैसे गंभीर अपराधों पर माननीय न्यायालय ने कड़ा रुख अपनाते हुए पिछले पांच महीनों में 17 हत्या प्रकरणों में 29 आरोपियों को कठोर कारावास की सजा सुनाई है,भारतीय न्याय संहिता लागू होने के बाद यह कार्रवाई जिले में अपराधियों के लिए बड़ा संदेश मानी जा रही है कि अब केवल गवाहों के भरोसे नहीं, बल्कि वैज्ञानिक और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर भी अपराधियों को सजा मिल रही है।

डेयरी फार्म में महिला हत्या,आरोपी को उम्रकैद- ग्राम पसला स्थित डेयरी फार्म में हुई महिला हत्या के मामले में न्यायालय ने आरोपी को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास और अर्थदंड से दंडित किया, मामले में प्रस्तुत परिस्थितिजन्य और वैज्ञानिक साक्ष्य न्यायालय के फैसले का आधार बने।

नावापारा हत्या कांड में 10 वर्ष की सजा-कॉलेज रोड नावापारा सूरजपुर स्थित एक मकान में महिला की हत्या मामले में आरोपी को न्यायालय ने 10 वर्ष की कठोर कारावास की सजा सुनाई, न्यायालय ने कहा कि घरेलू विवाद या व्यक्तिगत तनाव हत्या का औचित्य नहीं बन सकता।

पत्नी ने पति की हत्या की,मिली उम्रकैद- चौकी लटोरी क्षेत्र के ग्राम द्वारिकापुर गाड़ा झरिया में पत्नी द्वारा धारदार हथियार से पति की हत्या किए जाने के मामले में न्यायालय ने आरोपी महिला को आजीवन कारावास की सजा सुनाई, यह मामला पूरे क्षेत्र में काफी चर्चित रहा था।

जमीन विवाद बना मौत की वजह- थाना चांदनी क्षेत्र के ग्राम विशालपुर में जमीन विवाद को लेकर चार लोगों ने मिलकर एक व्यक्ति की हत्या कर दी थी,न्यायालय ने चारों आरोपियों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

चाचा ने भतीजे की ली जान- ग्राम अवन्तिकापुर में पारिवारिक विवाद के चलते चाचा द्वारा भतीजे की हत्या करने के मामले में न्यायालय ने आरोपी को 7 वर्ष की कठोर कारावास की

सजा सुनाई,न्यायालय ने टिप्पणी की कि पारिवारिक रिश्तों में हिंसा समाज के लिए गंभीर चिंता का विषय है।

पेड़ से बांधकर बेटे की हत्या

थाना सूरजपुर के ग्राम परीं गौटियापारा में एक युवक को उसके पिता और भाई द्वारा पेड़ से बांधकर मारपीट कर हत्या कर देने का मामला बेहद सनसनीखेज रहा,न्यायालय ने दोनों आरोपियों को 10-10 वर्ष की कठोर कारावास की सजा सुनाई।

अब गवाह पलटे तो भी बचना मुश्किल

इन मामलों में सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह रहा कि कई प्रकरणों में चश्मदीद गवाहों के बयान बदलने के बावजूद न्यायालय ने अन्य मजबूत साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों को दोषी माना,मेडिकल रिपोर्ट, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, परिस्थितिजन्य साक्ष्य,डिजिटल रिकॉर्ड,फोरेंसिक जांच और तकनीकी विश्लेषण अब न्यायिक प्रक्रिया में निर्णायक भूमिका निभा रहे हैं।

अपराधियों को स्पष्ट संदेश-

नए कानून लागू होने के बाद न्यायालयों की कार्यशैली में तेजी और सख्ती दोनों देखने को मिल रही है,अब अपराध के बाद गवाहों को प्रभावित कर मामला कमजोर करने की पुरानी रणनीति उतनी कारगर नहीं रह गई है, सूरजपुर न्यायालय के इन फैसलों को कानून व्यवस्था और न्यायिक प्रक्रिया में बढ़ते वैज्ञानिक दृष्टिकोण का बड़ा उदाहरण माना जा रहा है।

सायं सरकार का राजनीतिक सरेंडर

सूरजपुर में झुका प्रशासनिक अहंकार, जीती जनता की आवाज

कांग्रेस ने प्रशासन द्वारा मांगें मानने को बताया जनशक्ति और लोकतंत्र की जीत

-संवाददाता-
बलरामपुर,29 मई 2026 (घटती-घटना)।

जिला कांग्रेस कमेटी बलरामपुर के उपाध्यक्ष सुनील सिंह ने सूरजपुर जिला प्रशासन द्वारा कांग्रेस कमेटी तथा पूर्व उपमुख्यमंत्री टी.एस. सिंहदेव और कांग्रेस नेता दीपक बैच की मांगों को स्वीकार किए जाने पर जनता को बधाई देते हुए इसे लोकतंत्र और जनसंघर्ष की बड़ी जीत बताया है। जारी प्रेस विज्ञप्ति में उन्होंने कहा कि यह किसी एक राजनीतिक दल की नहीं, बल्कि जनता की सामूहिक शक्ति, लोकतांत्रिक मूल्यों और जनआवाज की ऐतिहासिक विजय है। उन्होंने कहा कि जिस प्रशासन ने शुरुआत में जनभावनाओं को अनसुना करने का प्रयास किया, वही अंततः जनता के दबाव और सत्य की ताकत के सामने झुकने को मजबूर हो गया। सुनील सिंह ने कहा कि यह घटना स्पष्ट संदेश देती है कि सत्ता चाहे कितनी भी अहंकारी क्यों न हो जाए, लोकतंत्र में अंतिम निर्णय जनता की आवाज ही करती है। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ प्रशासनिक अधिकारी राजनीतिक दबाव में आकर निष्पक्षता और संवैधानिक मर्यादाओं को भूल जाते हैं, जो लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। उन्होंने कहा कि प्रशासन का दायित्व जनता के प्रति जवाबदेह रहना है, न कि किसी राजनीतिक दल या सत्ता के इशारों पर कार्य करना। जब प्रशासनिक तंत्र सत्ता की कठपुतली बनने लगता है,तब जनता का विश्वास कमजोर पड़ता है और लोकतंत्र भी प्रभावित होता है। कांग्रेस नेता ने प्रशासनिक अधिकारियों एवं कर्मचारियों से भावुक अपील करते हुए कहा कि सरकारें आती-जाती रहती हैं, सत्ता स्थायी नहीं होती, लेकिन प्रशासनिक पद की गरिमा,ईमानदारी और जनता का विश्वास हमेशा कायम रहता है। इसलिए अधिकारियों को किसी भी राजनीतिक दबाव, भय अथवा प्रलोभन में आए बिना संविधान और जनहित के अनुरूप कार्य करना चाहिए। उन्होंने कहा कि जनता सब देख रही है – कौन सत्ता के सामने झुक रहा है और कौन सत्य के साथ खड़ा है। सूरजपुर की घटना ने यह साबित कर दिया है कि जब जनता जागती है, तब सत्ता का अहंकार टूट जाता है और प्रशासन को भी जनभावनाओं के आगे झुकना पड़ता है। सुनील सिंह ने कहा कि कांग्रेस पार्टी हमेशा जनता की आवाज बनकर अन्याय, दमन और राजनीतिक दबाव के खिलाफ संघर्ष करती रहेगी। लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि है और जनता की जीत ही कांग्रेस की सबसे बड़ी ताकत है।

सुशासन शिविर बना बवाल का मैदान ! काला झंडा और काली पट्टी लेकर पहुंचे ग्रामीण,प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी

जिला पंचायत सदस्य सुरेश आयाम हिरासत में...टुकुडांड की घटना से पूरे प्रतापपुर में मचा राजनीतिक भूचाल

-सोनू कश्यप-
प्रतापपुर,29 मई 2026 (घटती-घटना)।

प्रतापपुर विकासखंड के टुकुडांड में आयोजित जिला स्तरीय जन समस्या निवारण एवं सुशासन त्यौहार शिविर शुक्रवार को अचानक उस समय हंगामे और भारी विवाद में बदल गया, जब जिला पंचायत सदस्य एवं किसान नेता सुरेश आयाम अपने समर्थकों और बड़ी संख्या में ग्रामीणों के साथ काला झंडा और हाथों में काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन करने पहुंच गए। 'सुशासन त्योहार ढकोसला है', 'किसानों को न्याय दो', 'जनता की समस्याओं का समाधान करो' और 'भ्रष्टाचार बंद करो' जैसे नारों से पूरा शिविर स्थल गूंज उठा। अचानक हुए इस उग्र विरोध प्रदर्शन से प्रशासनिक अमले में हड़कंप मच गया और कुछ ही देर में पूरा कार्यक्रम तनावपूर्ण माहौल में बदल गया। प्रतापपुर क्षेत्र में इस तरह का उग्र विरोध पहली बार देखने को मिला, जिसके बाद यह मामला पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बन गया है। जानकारी के अनुसार जिला प्रशासन द्वारा टुकुडांड में बड़े स्तर पर जन समस्या निवारण शिविर आयोजित किया गया था। शिविर में ग्रामीणों की समस्याओं के समाधान,शासन की योजनाओं की जानकारी तथा विभागीय शिकायतों के निराकरण का दावा किया जा रहा था। कार्यक्रम में प्रतापपुर और जिले के कई वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी,विभागीय कर्मचारी तथा जनप्रतिनिधि मौजूद थे। इसी दौरान जिला पंचायत सदस्य सुरेश आयाम अपने समर्थकों और ग्रामीणों के साथ मौके पर पहुंचे। सभी प्रदर्शनकारी विरोध जताने के लिए हाथों में काला झंडा और बांहों पर काली पट्टी बांधे हुए थे। शिविर स्थल पहुंचते ही प्रदर्शनकारियों ने प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। प्रदर्शनकारियों का आरोप था कि क्षेत्र में किसानों को खाद नहीं मिल रही है, जल जीवन मिशन के कई कार्य अधूरे पड़े हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल संकट बना हुआ है और सड़क

व्यवस्था पूरी तरह बदहाल हो चुकी है। इसके अलावा विभिन्न विभागों में कथित भ्रष्टाचार और लापरवाही को लेकर भी प्रदर्शनकारियों ने प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए। ग्रामीणों का कहना था कि कई बार विभागीय अधिकारियों और प्रशासन को ज्ञापन सौंपने के बावजूद समस्याओं का समाधान नहीं हुआ, जिससे मजबूर होकर उन्हें विरोध प्रदर्शन करना पड़ा। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार प्रदर्शन के दौरान जिला पंचायत सदस्य सुरेश आयाम और प्रशासनिक अधिकारियों के बीच तीखी बहस भी हुई। प्रदर्शनकारियों का आरोप था कि अधिकारी केवल कागजों में सुशासन का दावा कर रहे हैं,जबकि जमीनी स्तर पर आम जनता परेशान है। मौके पर मौजूद अधिकारियों ने प्रदर्शनकारियों को शांत कराने और समझाने का प्रयास किया,लेकिन प्रदर्शनकारी लगातार नारेबाजी करते रहे। कुछ देर के लिए शिविर स्थल का माहौल पूरी तरह तनावपूर्ण हो गया और कार्यक्रम में अफरा-तफरी जैसी स्थिति निर्मित हो गई। स्थिति बिगड़ते देख प्रतापपुर पुलिस ने हस्तक्षेप किया। पुलिस अधिकारियों के निर्देश पर प्रदर्शनकारियों को हटाने की कार्रवाई शुरू की गई। इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच जमकर धक्का-मुक्की हुई। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक कई प्रदर्शनकारी पुलिस कार्रवाई का विरोध करते हुए जमीन पर बैठ गए और गिरफ्तारी देने से इनकार करने लगे। इसके बाद पुलिस ने बलपूर्वक कार्रवाई करते हुए जिला पंचायत सदस्य सुरेश आयाम सहित कई प्रदर्शनकारियों को खींचते-घसीटते हुए पुलिस वाहन में बैठाया और थाना प्रतापपुर ले गई। बताया जा रहा है कि थाना ले जाते समय भी प्रदर्शनकारी पूरे रास्ते प्रशासन और शासन के खिलाफ नारेबाजी करते रहे। थाना परिसर में भी कुछ देर तक हंगामे जैसी स्थिति बनी रही। बाद में स्थानीय पुलिस और अधिकारियों की समझाइश के बाद सभी प्रदर्शनकारियों को छोड़ दिया गया। हालांकि इस पूरी घटना के वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गए हैं। फेसबुक,इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप ग्रुपों में वायरल वीडियो को लेकर लोग तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। पूरे प्रतापपुर नगर और विकासखंड में यह मामला दिनभर चर्चा का विषय बना रहा। घटना के बाद क्षेत्र में राजनीतिक माहौल भी गरमा गया है। ग्रामीणों और समर्थकों ने प्रशासनिक कार्रवाई को जनआवाज दबाने का प्रयास बताया है। उनका कहना है कि यदि जनता अपनी समस्याएं भी नहीं उठा सकती,तो सुशासन शिविर आयोजित करने का क्या औचित्य है। वहीं प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि सरकारी कार्यक्रम में व्यवधान उत्पन्न होने और कानून व्यवस्था बिगड़ने की आशंका के चलते आवश्यक कार्रवाई की गई। अधिकारियों के मुताबिक स्थिति नियंत्रण से बाहर जा रही थी, इसलिए पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा। टुकुडांड में हुए इस हाईवोल्टेज हंगामे ने सुशासन त्यौहार की कार्यप्रणाली और प्रशासनिक संवेदनशीलता पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि यदि उनकी समस्याओं का जल्द समाधान नहीं हुआ,तो आने वाले दिनों में आंदोलन और उग्र हो सकता है।

फिलहाल पूरे क्षेत्र की नजर अब प्रशासन के अगले कदम और किसानों-ग्रामीणों की मांगों पर टिकी हुई है।

न्यायालय नजूल अधिकारी अम्बिकापुर,जिला-सरगुजा.

रा.प्र.क्र./अ-20(1)/2025-26

ईश्तहार

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक राजेश अग्रवाल आ0/पति घनश्याम दास अग्रवाल जाति निवासी ब्रम्ह रोड़ अम्बिकापुर, तहसील अम्बिकापुर, जिला सरगुजा छ0ग0 के द्वारा मोहल्ला - राममंदिर मैदान, शीट नम्बर-11क नगर अम्बिकापुर स्थित नजूल प्लाट नम्बर 3196/4813/77 रकबा 0.03 एकड़ भूमि का लीज अवधि दिनांक 31.3.2026 को समाप्त हो गई है। जिस कारण लीज अवधि बढ़ाने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है।

अतः उक्त के संबंध में यदि किसी व्यक्ति अथवा संस्था को कोई दावा अथवा आपत्ति हो तो अपना लिखित दावा / आपत्ति स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से दिनांक-10.06.2026 तक इस न्यायालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकते है। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा / आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेंगा ।

आज दिनांकः- 21.05.2026 को मेरे हस्ताक्षर एंव न्यायालीन पदमुद्रा से जारी ।

सील

नजूल अधिकारी ,अंबिकापुर

फर्जी निवास प्रमाण पत्र रैकेट का पर्दाफाश...छत्तीसगढ़ कोटे से केंद्रीय बलों में भर्ती कराने वाला गिरोह बेनकाब,मुख्य आरोपी समेत 4 गिरफ्तार

-संवाददाता-
बलरामपुर,29 मई 2026 (घटती-घटना)।

छत्तीसगढ़ राज्य का फर्जी निवास प्रमाण-पत्र बनवाकर केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में अवैध भर्ती कराने वाले बड़े गिरोह का बलरामपुर पुलिस ने पर्दाफाश किया है। मामले में अब तक मुख्य आरोपी समेत चार आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। जांच में खुलासा हुआ है कि गिरोह डोंगरगढ़ और अन्य स्थानों से कूटरचित दस्तावेज तैयार कर गैर-निवासियों को छत्तीसगढ़ का निवासी दर्शाकर सीआरपीएफ,एसएसबी और सीआईएसएफ जैसी केंद्रीय एजेंसियों में भर्ती करवा रहा था। पुलिस के मुताबिक यह पूरा खेल इसलिए खेला जा रहा था क्योंकि केंद्रीय भर्ती में छत्तीसगढ़ राज्य का कटऑफ अन्य राज्यों की तुलना में कम रहता है। इसी का फायदा उठाकर दूसरे राज्यों के युवकों को फर्जी तरीके से

छत्तीसगढ़ का निवासी बनाकर नौकरी दिलाई जा रही थी।

तहसीलदार की शिकायत से खुला बड़ा खेल : मामले का खुलासा उस समय हुआ जब 28 अप्रैल 2026 को तहसीलदार बलरामपुर ने थाना बलरामपुर में लिखित शिकायत दी। शिकायत में बताया गया कि 204 कोबरा बटालियन सीआरपीएफ करनपुर जगदलपुर में पदस्थ कांस्टेबल सुमित पिता अचल सिंह द्वारा ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के माध्यम से फर्जी तरीके से स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र बनवाया गया है। जांच में पाया गया कि आरोपी ने विशाल सोनी के शैक्षणिक एवं अन्य दस्तावेजों में कूट रचना कर अपना नाम जोड़ते हुए छत्तीसगढ़ का निवास प्रमाण पत्र जारी करवाया था। शिकायत के आधार पर थाना बलरामपुर में अपराध क्रमांक 78/2026 के तहत बीएनएस की विभिन्न धाराओं और आईटी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई।

राजस्थान निवासी आरोपी पहले ही हो चुका था भर्ती : विवेचना के दौरान सामने आया कि आरोपी सुमित पिता अचल सिंह, निवासी ग्राम रुंध जिला धौलपुर (राजस्थान),फर्जी दस्तावेजों के आधार पर वर्ष 2023 में एसएससी माध्यम से सीआरपीएफ में भर्ती हो चुका था। पुलिस ने आरोपी को 14 मई 2026 को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया।

रायपुर से पकड़े गए मास्टरमाइंड : जांच आगे बढ़ने पर पुलिस ने गिरोह के मुख्य आरोपी विवेक सिंह तोमर और उसके साथी आकाश सिंह शर्मा को रायपुर से हिरासत में लिया।

पुलिस जांच में खुलासा हुआ कि...

- विवेक सिंह तोमर ने स्वयं भी डोंगरगढ से फर्जी दस्तावेजों के जरिए छत्तीसगढ का निवास प्रमाण-पत्र बनवाया था।
- आकाश शर्मा ने अपना नाम बदलकर 'तुकेश्वर पिता भोजराज' के नाम से फर्जी आधार कार्ड और पैन कार्ड तैयार कराया।
- बलरामपुर निवासी दीपक चौरसिया के शैक्षणिक दस्तावेजों में छेड़छाड़ कर फर्जी पहचान बनाई गई।
- इसके आधार पर तहसील कार्यालय बलरामपुर से स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र जारी कराया गया।

न्यायालय नजूल अधिकारी अम्बिकापुर,जिला-सरगुजा.

रा.प्र.क्र./अ-6/2025-26

ईश्तहार

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक राजेश अग्रवाल पिता घनश्याम दास अग्रवाल, उम्र- 57 वर्ष, निवासी ब्रम्हरोड़, था0तह0 अम्बिकापुर जिला सरगुजा छ0ग0 के द्वारा तदाशय का आवेदन प्रस्तुत किया गया है, कि आवेदक एवं अनावेदकगण संजय अग्रवाल, अजय गर्ग पिता घनश्याम दास अग्रवाल, घनश्याम दास अग्रवाल, पिता स्व. खजांचीलाल अग्रवाल, सभी निवासी ब्रम्हरोड़ अम्बिकापुर, जिला सरगुजा छ0ग0 के संयुक्त स्वामित्व व अधिपत्य की नगर अम्बिकापुर, शीट नं. 11क, मोहल्ला - राम मंदिर मैदान स्थित नजूल भूमि प्लॉट नंबर 3196/4813/77 रकबा 0.03 ऐ0 भूमि / दुकान के संबंध में अनावेदकगण द्वारा अपने हक व हिस्से की भूमि का पंजीबद्ध हकत्याग पत्र दिनांक 21.04.2026 का निष्पादन आवेदक के पक्ष में किया गया है। अतः उक्त पंजीबद्ध हकत्याग पत्र के आधार पर आवेदित भूमि से अनावेदकगण का नाम विलोपित कराकर एकल स्वामी के रूप में आवेदक स्वयं का नाम रिकार्ड पर दुरूस्त किये जाने हेतु आवेदक द्वारा पंजीबद्ध हकत्याग पत्र की छायाप्रति मय दस्तावेज सहित आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 109, 110 छ.ग. भू-राजस्व संहिता 1959 के तहत प्रस्तुत किया गया है।

अतः उक्त सबंध में जिस किसी व्यक्ति या संस्था को कोई दावा अथवा आपत्ति हो तो वे अपना लिखित दावा / आपत्ति स्वंय अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से दिनांक- 10/06 / 2026 तक इस न्यायालय में प्रस्तुत कर सकतें हैं । नियत तिथि के पश्चात प्राप्त दावा / अपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

आज दिनांक-26/05/2026 को मेरे न्यायालयीन मुद्रा एंव हस्ताक्षर से जारी किया गया।

सील

नजूल अधिकारी ,अंबिकापुर

खेतों तक नहीं पहुँची खाद,लेकिन बिचौलियों तक कैसे पहुँची? 246.75 मेट्रिक टन घोटाले पर गरमाई राजनीति

किसानों की खाद पर किसका कब्जा? गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने खोला मोर्चा

गोदाम खाली, किसान परेशान और अब खुल रहा खाद घोटाले का राज

खाद घोटाले में नए नामों की चर्चा,कार्रवाई नहीं होने पर उठे सवाल

246.75 मेट्रिक टन खाद का खेलः किसान लाइन में...बिचौलियों के गोदाम फुल!

खाद घोटाले पर राजनीतिक संग्राम : दोषियों पर कार्रवाई नहीं तो आंदोलन की चेतावनी

किसानों का हक कौन खा गया? खाद घोटाले में निष्पक्ष जांच की मांग तेज

-राजेन्द्र शर्मा-

खड़गवां, 29 मई 2026 (घटती-घटना)।

गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने जिल्दा सहकारी समिति में सामने आए 246.75 मेट्रिक टन खाद घोटाले को लेकर अब प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है,पार्टी के पदाधिकारी पोड़ी बचरा चौकी पहुंचे और लिखित शिकायत सौंपते हुए पूरे मामले की निष्पक्ष जांच तथा दोषियों पर कठोर कार्रवाई की मांग की,जिस खाद को किसानों के खेतों तक पहुंचना था,वह अब राजनीतिक गलियारों और पुलिस जांच के बीच घूमती दिखाई दे रही है,ग्रामीणों का आरोप है कि किसानों को जरूरत के समय खाद नहीं मिली,लेकिन गोदामों से खाद रहस्यमयी तरीके से गायब होती रही। अब सवाल यह उठ रहा है कि आखिर किसानों के हिस्से की खाद किन लोगों के घर और गोदाम तक पहुंची?

यह घोटाला नहीं,किसानों के अधिकारों की लूट

गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के नेताओं ने आरोप लगाया कि खाद की अवैध खरीदी-बिक्री कर लाखों रुपये का खेल किया गया है, पार्टी का कहना है कि यह केवल आर्थिक घोटाला नहीं बल्कि किसानों के अधिकारों पर सीधा हमला है, पार्टी पदाधिकारियों ने कहा कि समिति में खाद वितरण के नाम पर बड़े स्तर पर गड़बड़ी की गई,जिन किसानों को खाद मिलनी चाहिए थी,वे लाइन में खड़े रहे और दूसरी तरफ कथित रूप से बिचौलियों और रसूखदार लोगों तक खाद पहुंचती रही, व्यंग्यात्मक अंदाज में ग्रामीण अब कह रहे हैं कि खाद खेत में कम और सेटिंग में ज्यादा इस्तेमाल हुई।

घटती घटना
सरगुजा,सूरजपुर कोरिया समाचार
किसानों की खाद या नेताओं-बिचौलियों की दावत?
1800 बोरी खाद बेचने की कबूली बात से मचा हड़कंप
खाद घोटाले में खुलती जा रही नई परतें
ग्रामीणों में नाराजगी, निष्पक्ष जांच की मांग

दोषियों को बचाने की कोशिश?

शिकायत पत्र में समिति अध्यक्ष,प्रबंधक और कर्मचारियों की भूमिका की जांच की मांग की गई है,पार्टी नेताओं का आरोप है कि पूरे मामले में कई लोगों की मिलीभगत सामने आ रही है,लेकिन कार्रवाई कुछ चुनिंदा लोगों तक सीमित रखी जा रही है,ग्रामीणों और किसानों के बीच यह चर्चा तेज है कि जिन लोगों के पास से खाद बरामद हुई या जिनके नाम सामने आए, उन पर अब तक कठोर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? क्या प्रशासन बड़े नामों तक पहुंचने से बच रहा है? क्या राजनीतिक दबाव जांच की दिशा तय कर रहा है? यही सवाल अब गांव-गांव में चर्चा का विषय बन गए हैं।

पुलिस जांच से बढ़ा दबाव

बताया जा रहा है कि पुलिस पहले से खाद स्टॉक,वितरण रजिस्टर और खरीदी-बिक्री से जुड़े दस्तावेजों की जांच कर रही है,लेकिन गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की सक्रियता के बाद अब प्रशासन पर निष्पक्ष कार्रवाई का दबाव और बढ़ गया है,पार्टी नेताओं ने साफ चेतावनी दी है कि यदि जल्द ठोस कार्रवाई नहीं हुई तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा,उनका कहना है कि किसानों के नाम पर होने वाले भ्रष्टाचार को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

ग्रामीणों में गुस्सा,किसानों में अविश्वास

ग्रामीणों का कहना है कि जब खेती का समय था तब उन्हें खाद के लिए चक्कर लगवाए गए,कई किसानों को यह कहकर लौटा दिया गया कि स्टॉक खत्म हो गया है,लेकिन अब जब हजारों बोरी खाद के गायब होने की बात सामने आ रही है तो लोगों का भरोसा सहकारी व्यवस्था पर कमजोर पड़ता दिखाई दे रहा है,किसानों का आरोप है कि यदि समय पर निष्पक्ष जांच नहीं हुई तो भविष्य में भी इसी तरह खाद,बीज और अन्य कृषि सामग्री में भ्रष्टाचार जारी रहेगा।

अब प्रशासन की परीक्षा

246.75 मेट्रिक टन खाद घोटाला अब केवल सहकारी समिति तक सीमित मामला नहीं रह गया है, यह किसानों के भरोसे, प्रशासन की निष्पक्षता और राजनीतिक जवाबदेही का बड़ा सवाल बन चुका है, अब देखना यह होगा कि जांच केवल कागजों तक सीमित रहती है या सच में उन लोगों तक पहुंचती है जिनके संरक्षण में किसानों की खाद गायब होती रही, फिलहाल गांवों में एक ही चर्चा है अगर किसानों की खाद भी सुरक्षित नहीं, तो फिर सहकारी व्यवस्था आखिर किसके लिए चल रही है?

गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की प्रमुख मांगें...

- पूरे खाद घोटाले की निष्पक्ष और उच्चस्तरीय जांच कराई जाए...
- दोषी अधिकारियों,कर्मचारियों और बिचौलियों पर एफआईआर दर्ज हो...
- अवैध तरीके से खाद खरीदने वालों की पहचान कर कार्रवाई की जाए...
- किसानों के नुकसान की भरपाई सुनिश्चित की जाए...
- पूरे मामले की जांच सार्वजनिक रूप से पारदर्शी तरीके से हो...

नगर निगम सो रहा,जनता रो रही–पानी, सड़क और सफाई संकट पर इण्टक व लोकमंच का निगम प्रशासन पर तीखा हमला

चिरमिरी में मूलभूत सुविधाओं का संकट गहराया

-संवाददाता-
चिरमिरी,29 मई 2026
(घटती-घटना)।

चिरमिरी शहर में पानी,बिजली,सड़क और साफ-सफाई जैसी मूलभूत सुविधाओं को लेकर जनता की परेशानी अब खुलकर सामने आने लगी है, शहर के कई क्षेत्रों में हालात ऐसे हैं मानो नगर निगम और प्रशासन ने जिम्मेदारियों से हाथ खड़े कर दिए हों, जगह-जगह टूटी सड़कें,गड्ढों में तब्दील मार्ग,पेयजल संकट और सफाई व्यवस्था की बदहाली को लेकर कांग्रेस समर्थित श्रमिक संगठन साऊथ ईस्टर्न कोयला मजदूर कांग्रेस (इण्टक) और सामाजिक संगठन लोकमंच ने नगर निगम प्रशासन पर तीखा हमला बोला है।

जनता परेशान,अधिकारी प्रस्ताव बनाने में व्यस्त

संगठनों का आरोप है कि शहर की समस्याओं से नगर निगम के अधिकारी भलीभांति परिचित हैं,लेकिन समाधान के बजाय वे केवल प्रस्ताव भेजने और स्वीकृति आने की औपचारिक दलील देकर जिम्मेदारी से बच रहे हैं,गोदरीपारा और हल्दीबाड़ी जैसे प्रमुख क्षेत्रों में पानी की गंभीर समस्या को लेकर जनता को धरना देने तक की नौबत आ चुकी है,संगठनों का कहना है कि बरसात शुरू होने से पहले यदि सड़कों की मरम्मत नहीं हुई तो हालात और भयावह हो जाएंगे।

38 सूत्रीय मांगपत्र से निगम प्रशासन पर दबाव

इण्टक अध्यक्ष अब्दुल सलीम और लोकमंच अध्यक्ष एवं पूर्व महापौर के. डोमरू रेड्डी ने नगर निगम आयुक्त रामप्रसाद आंचला को 38 बिंदुओं का विस्तृत ज्ञापन सौंपा था, मांगों पर कोई ठोस पहल नहीं होने के बाद अब स्मरण पत्र देकर 15 दिनों के भीतर कार्रवाई की चेतावनी दी गई है, संगठनों ने स्पष्ट कहा है कि यदि समस्याओं का निराकरण नहीं हुआ तो नगर निगम की हठधर्मिता के खिलाफ बड़ा आंदोलन किया जाएगा।

स्वच्छ भारत मिशन फेल,जनता बेहाल

संगठनों ने आरोप लगाया कि नगर निगम की लापरवाही के कारण स्वच्छ भारत मिशन की स्थिति शहर में बदहाल हो चुकी है,कई क्षेत्रों में नियमित सफाई नहीं हो रही, सार्वजनिक शौचालय बदहाल हैं और सड़कें गड्ढों में तब्दील हो चुकी हैं,व्यंग्यात्मक अंदाज में लोगों का कहना है कि शहर में विकास के बोर्ड जरूर दिखते हैं, लेकिन जमीन पर जनता को गड्ढे,गंदगी और पानी संकट ही दिखाई देता है।

आंदोलन की चेतावनी

इण्टक और लोकमंच ने कलेक्टर, एसडीएम, तहसीलदार और थाना प्रभारी को भी पत्र की प्रतिलिपि भेजते हुए प्रशासन को आगाह किया है कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो जनता के साथ मिलकर आंदोलन किया जाएगा, अब देखने वाली बात यह होगी कि नगर निगम प्रशासन इन मांगों को गंभीरता से लेकर समाधान की दिशा में कदम उठाता है या फिर चिरमिरी की जनता को एक और बरसात टूटी सड़कों और अधूरी सुविधाओं के बीच गुजारनी पड़ेगी।

सिर्फ सड़क-पानी नहीं, कर्मचारियों और व्यवस्थाओं का मुद्दा भी उठाया

ज्ञापन में केवल मूलभूत सुविधाओं ही नहीं,बल्कि निगम की कार्यप्रणाली और कथित अव्यवस्थाओं को भी प्रमुखता से उठाया गया है,संगठनों ने ठेका कर्मचारियों के नियमित वेतन भुगतान,बीमा सुविधा,मृत कर्मचारी बाबूलाल के परिजनों को बीमा राशि देने,पीलिया से मृत लोगों के परिवारों को मुआवजा देने तथा फायर स्टेशन में बेकार पड़ी खरीदी गई सामग्रियों की जांच की मांग की है,इसके अलावा शहर की सिटी बस सेवा,एम्बुलेंस, शव वाहन व्यवस्था,पानी टंकियों की सफाई,सार्वजनिक शौचालयों की दुर्दशा,मुक्तिधाम में लकड़ी की व्यवस्था और सड़क सुरक्षा संसाधनों की खराब स्थिति पर भी सवाल उठाए गए हैं।

निर्माणाधीन 200 बिस्तरीय जिला अस्पताल का कलेक्टर ने किया निरीक्षण,लंबे इंतजार के बाद फिर जागी उम्मीद

चार साल की धीमी रफ्तार के बाद अब तेज होगी स्वास्थ्य व्यवस्था की चाल

-संवाददाता-
बैकुंठपुर,29 मई 2026
(घटती-घटना)।

बैकुंठपुर में निर्माणाधीन 200 बिस्तरीय नवीन जिला चिकित्सालय एक बार फिर चर्चा में है,वर्षों से अधूरी पड़ी इस बहुप्रतीक्षित स्वास्थ्य परियोजना का गुरुवार को कोरिया कलेक्टर रोक्तिमा यादव ने निरीक्षण किया, निरीक्षण के दौरान उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि अब निर्माण कार्य में क्वॉलिटी और टाइमिंग पर किसी भी प्रकार का समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा,जिले के लोगों के लिए यह अस्पताल केवल एक भवन नहीं,बल्कि बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं की उम्मीद है,लंबे समय से लोग आधुनिक जिला अस्पताल की मांग कर रहे थे,क्योंकि वर्तमान स्वास्थ्य व्यवस्था बढ़ती आबादी और मरीजों के दबाव के मुकाबले काफी सीमित मानी जा रही है।

जानकारी के अनुसार जिला खनिज संस्थान न्यास (डीएमएफ) द्वारा वर्ष 2021 में इस परियोजना के लिए लगभग 35 करोड़ रुपये की प्रशासकीय स्वीकृति दी गई थी, वहीं सीजीएमएससी लिमिटेड द्वारा करीब 31 करोड़ रुपये की तकनीकी स्वीकृति जारी की गई थी। निर्माण कार्य 10 मई 2022 से शुरू हुआ था,लेकिन सरकारी परियोजनाओं की पुरानी बीमारी फंड की कमी और धीमी गति यहां भी सामने आई,शुरुआती दौर में 13 करोड़ रुपये का आबंटन मिला और निर्माण शुरू हुआ, लेकिन बाद में अतिरिक्त राशि नहीं मिलने के कारण काम बीच में ही रुक गया, धीरे-धीरे निर्माणाधीन भवन अधूरा खड़ा रह गया और लोगों की उम्मीदें भी अधर में लटक गईं, अब हाल ही में डीएचएस मद से 23 करोड़ 59 लाख रुपये की स्वीकृति मिलने के बाद काम ने फिर रफ्तार पकड़ी है। निर्माण एजेंसी का दावा है कि अगले एक वर्ष में अस्पताल भवन तैयार कर लिया जाएगा।

कलेक्टर का सख्त संदेश–अब देरी नहीं चलेगी...

निरीक्षण के दौरान कलेक्टर रोक्तिमा यादव ने निर्माण एजेंसी और अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि अब काम में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी,उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री द्वारा हाल ही में स्वास्थ्य परियोजनाओं की समीक्षा की गई है,जिसमें गुणवत्ता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं,कलेक्टर ने कहा कि करोड़ों रुपये की लागत से बन रहे इस अस्पताल में निर्माण गुणवत्ता से किसी प्रकार का समझौता नहीं होना चाहिए,उन्होंने समयसीमा का पालन करने और तय मानकों के अनुरूप निर्माण कार्य करने पर विशेष जोर दिया।

आधुनिक सुविधाओं से लैस होगा अस्पताल

प्रस्तावित अस्पताल भवन तीन मंजिला होगा और इसमें आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाएं विकसित की जाएंगी,निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने ओपीडी, वार्ड,ऑपरेशन थिएटर,पैथोलॉजी लैब,एक्सरे कक्ष,सोनोग्राफी कक्ष, मेडिकल स्टोर,लिफ्ट,रैम्प और अन्य सुविधाओं की जानकारी ली,इसके साथ ही मरीजों और उनके परिजनों के लिए पार्किंग,कैंटीन,पेयजल, बिजली बैकअप और पानी निकासी जैसी मूलभूत व्यवस्थाओं पर भी चर्चा की गई, कलेक्टर ने अधिकारियों से कहा कि यह अस्पताल केवल भवन निर्माण तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि यहां आधुनिक जांच और उपचार सुविधाएं भी उपलब्ध होनी चाहिए ताकि लोगों को बड़े शहरों का रुख न करना पड़े।

बुजुर्गों और दिव्यांगजनों की सुविधा पर विशेष जोर

निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने विशेष रूप से बुजुर्गों और दिव्यांगजनों की सुविधाओं पर ध्यान देने के निर्देश दिए,उन्होंने कहा कि अस्पताल में रैम्प, लिफ्ट और आसान आवागमन की व्यवस्था प्राथमिकता के साथ सुनिश्चित की जाए,सरकारी अस्पतालों में अक्सर देखा जाता है कि मरीज इलाज से पहले ही सीढ़ियों और अव्यवस्था से परेशान हो जाते हैं, इसी को ध्यान में रखते हुए कलेक्टर ने निर्देश दिए कि अस्पताल ऐसा बने जहां हर व्यक्ति आसानी से पहुंच सके।

स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर नई उम्मीद

कोरिया जिले के लोग लंबे समय से बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं की मांग करते रहे हैं, गंभीर मरीजों को अक्सर अंबिकापुर,बिलासपुर या रायपुर रेफर करना पड़ता है,ऐसे में 200 बिस्तरीय आधुनिक जिला अस्पताल का निर्माण क्षेत्र के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है,स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि अस्पताल समय पर पूरा हो जाता है और यहां पर्याप्त डॉक्टर, उपकरण तथा आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं,तो हजारों मरीजों को बेहतर इलाज मिल सकेगा।

अब जनता की नजर निर्माण की रफ्तार पर...

हालांकि निरीक्षण और निर्देशों के बाद उम्मीद जरूर बढ़ी है,लेकिन जनता अब केवल घोषणाएं नहीं बल्कि जमीन पर परिणाम देखना चाहती है, क्योंकि यह परियोजना पहले भी कई बार जल्द पूरा होगा के वादों के बीच धीमी पड़ चुकी है,अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या इस बार प्रशासनिक सख्ती और वित्तीय स्वीकृति के बाद अस्पताल तय समय पर बन पाएगा,या फिर यह परियोजना भी सरकारी फाइलों और अधूरे निर्माण की कहानी बनकर रह जाएगी,फिलहाल इतना तय है कि बैकुंठपुर का यह निर्माणाधीन अस्पताल अब सिर्फ ईंट और सीमेंट का ढांचा नहीं, बल्कि जिले की स्वास्थ्य व्यवस्था की सबसे बड़ी उम्मीद बन चुका है।

साहब! पोस्टर से उतरकर अब बोतल पर आइए...

सुशासन तिहार में जनता ने सरकार को दिया हाई स्पिरिट वाला सुझाव

जब सुशासन शिविर बना 'जनता का स्टैंड-अप कॉमेडी मंच'

एसी पर सब्सिडी और शराब की बोतल पर सीएम की तस्वीर,ग्रामीणों की मांगों ने उड़ाए अफसरों के होश

पोस्टर से निकलकर अब बोतल तक पहुँची राजनीति! सुशासन शिविर में गूंजी अनोखी मांग

साहब! गर्मी में जनता पिघल रही है...ग्रामीणों ने मांगी एसी-कूलर पर सरकारी छूट

जब जनता ने व्यंग्य में सुनाया सिस्टम का सच...लटमा शिविर बना चर्चा का केंद्र

सरकारी दफ्तर में पसीना नहीं,ठंडी हवा चाहिए,ग्रामीणों ने प्रशासन को दिया 'कूल' सुझाव

-रवि सिंह-

कोरिया,29 मई 2026
(घटती-घटना)।

लटमा में लगा सुशासन तिहार शिविर इस बार सरकारी योजनाओं से ज्यादा जनता की कल्पनाशक्ति और व्यंग्यात्मक मांगों के कारण चर्चा में आ गया, आमतौर पर ऐसे शिविरों में राशन कार्ड,सड़क, बिजली, पानी और पेंशन की शिकायतें सुनाई देती हैं,लेकिन इस बार ग्रामीणों ने ऐसा रचनात्मक लोकतंत्र दिखाया कि अधिकारी भी फाइल से ज्यादा चेहरों को पढ़ते नजर आए,यह शिविर सरकारी प्रशासन कम और जनता का खुला मंच ज्यादा दिखाई दिया, जहां ग्रामीणों ने व्यवस्था पर अपनी नाराजगी भी जताई और हास्य के जरिए सिस्टम को आईना भी दिखा दिया।

जब हर योजना पर फोटो है,तो शराब की बोतल क्यों पीछे?

शिविर की सबसे चर्चित मांग वह रही जिसने पूरे माहौल को हंसी और व्यंग्य से भर दिया,एक आवेदन में मांग की गई कि शराब की बोतलों पर मुख्यमंत्री और आबकारी मंत्री की तस्वीर छापी जाए, अब यह मांग सुनकर कुछ अधिकारी मुस्कुराए,कुछ ने सिर झुका लिया और कुछ ने शायद मन ही मन सोचा जनता अब बहुत समझदार हो गई है,ग्रामीणों का तर्क भी कमाल का था,उनका कहना था कि जब सरकार की हर योजना,पोस्टर, दीवार,राशन दुकान,पाइपलाइन और शौचालय तक पर नेताओं की तस्वीर लग सकती है, तो फिर शराब विभाग की पहचान बोतल पर क्यों नहीं होनी चाहिए? एक ग्रामीण ने मजाकिया अंदाज में कहा सरकार अगर हर चीज का श्रेय लेती है, तो फिर शाम की खुशी में भी जनता को पता होना चाहिए कि आशीर्वाद किसका है,यह मांग सिर्फ हास्य नहीं थी,बल्कि उस राजनीतिक संस्कृति पर तीखा व्यंग्य भी थी जिसमें प्रचार कभी-कभी काम से बड़ा दिखाई देने लगता है।

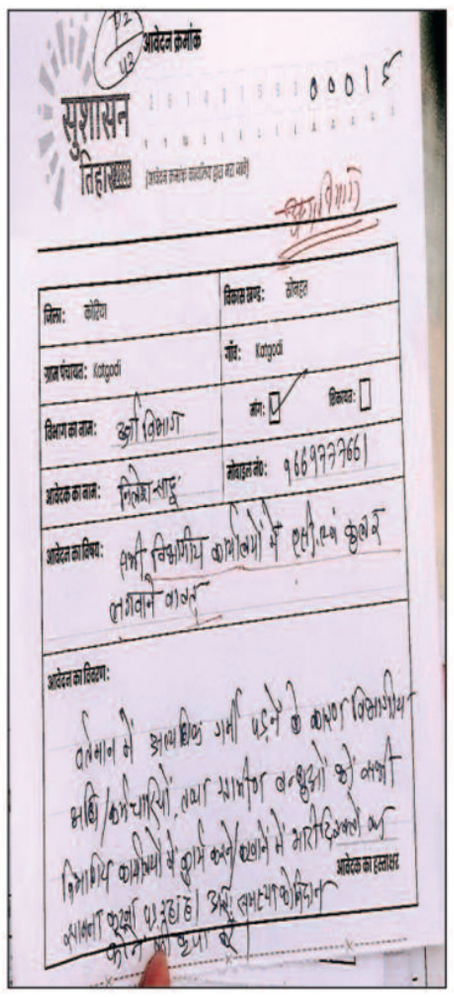

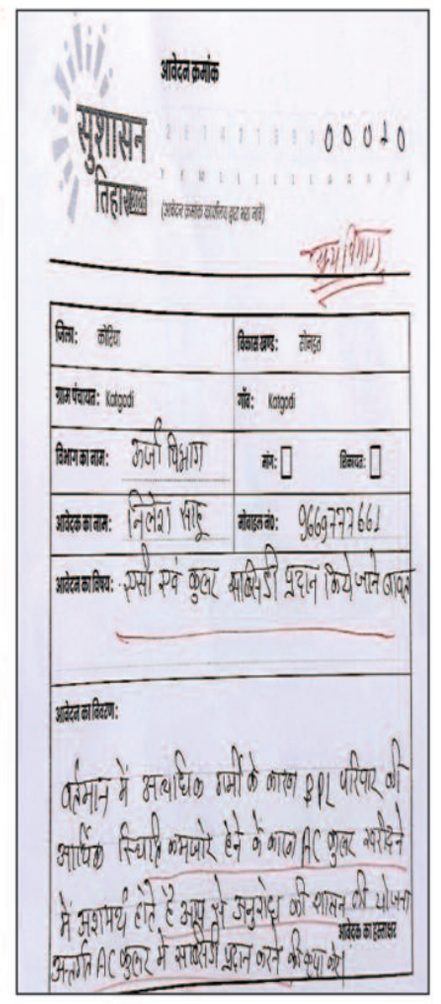

गरीब पसीने में पिघल रहा,अमीर एसी में खिल रहा...

गर्मी ने इस बार लोगों का धैर्य भी पिघला दिया,इसलिए ग्रामीणों ने सीधे सरकार से कूलिंग पैकेज मांग लिया। आवेदन में कहा गया कि बीपीएल परिवारों को एसी और कूलर खरीदने पर भारी सब्सिडी दी जाए,ग्रामीणों का कहना था कि सरकार गैस सिलेंडर,राशन और मकान में सहायता देती है,तो फिर इस जानलेवा गर्मी से राहत देने के लिए एसी-कूलर पर सहायता क्यों नहीं? व्यंग्यात्मक अंदाज में एक बुजुर्ग ने कहा गरीब आदमी दिन में मजदूरी करे,रात में गर्मी से तड़पे और फिर सुबह वोट भी दे? थोड़ा ठंडा रहने का अधिकार तो मिलना चाहिए, इस मांग ने यह भी दिखाया कि अब ग्रामीण सिर्फ बुनियादी सुविधाओं तक सीमित नहीं रहना चाहते, वे भी आराम की जिंदगी को अपना अधिकार मानने लगे हैं।

सरकारी दफ्तरों के लिए भी 'ठंडी-ठंडी, कूल-कूल' योजना

ग्रामीणों ने केवल अपने घरों के लिए एसी नहीं मांगा,बल्कि सरकारी दफ्तरों के लिए भी कूलर और एसी की मांग रख दी। उनका तर्क बेहद व्यावहारिक था,लोगों ने कहा कि सरकारी दफ्तरों में घंटों लाइन में खड़े रहना पड़ता है,गर्मी में बुजुर्ग,महिलाएं और बच्चे बेहाल हो जाते हैं। अगर दफ्तरों में ठंडी हवा चलेगी तो जनता भी खुश रहेगी और बाबू लोग भी कम गुस्से में रहेंगे,एक युवक ने चुटकी लेते हुए कहा जब साहब का मूड ठंडा रहेगा, तभी फाइल जल्दी चलेगी,यह बयान सुनकर वहां मौजूद कुछ कर्मचारी मुस्कुरा दिए,क्योंकि उन्हें भी शायद इस बात में सच्चाई नजर आई।

बैंक के लिए भी गुहार,पैसा अपना,चक्कर भी अपना?

मजेदार मांगों के बीच कुछ बेहद गंभीर मुद्दे भी उठे। ग्रामीणों ने सोनहत क्षेत्र में जिला सहकारी केंद्रीय बैंक की शाखा खोलने की मांग की,लोगों का कहना था कि पैसे जमा करने और निकालने के लिए दूर-दूर तक जाना पड़ता है,कई बार पूरा दिन सिर्फ बैंक के चक्कर में निकल जाता है,एक किसान ने व्यंग्य करते हुए कहा सरकार कहती है डिजिटल बनो,लेकिन नेटवर्क गायब रहता है और बैंक कई किलोमीटर दूर।

साहब गांव में रहेंगे तो खेती भी सुधरेगी...

ग्रामीणों ने कृषि विस्तार अधिकारी के लिए शासकीय आवास बनाने की मांग भी रखी, उनका कहना था कि अधिकारी गांव में ही रहेंगे तो किसानों को समय पर सलाह और योजनाओं की जानकारी मिल सकेगी, किसानों की सोच साफ थी अगर अधिकारी शहर में रहेंगे और किसान खेत में, तो खेती का विकास फाइल में ही होगा।

स्पीड ब्रेकर की मांग,विकास की रफ्तार ठीक है,मौत की नहीं...

ग्रामीणों ने सड़क सुरक्षा को लेकर भी चिंता जताई,स्कूलों,बाजार और दुर्घटना संभावित स्थानों पर स्पीड ब्रेकर बनाने की मांग की गई, लोगों का कहना था कि सड़कें चाहे टूटी हों,लेकिन गाड़ियों की रफ्तार नहीं टूटती। ऐसे में हादसों का खतरा लगातार बढ़ रहा है।

सुशासन का असली आईना

लटमा का यह सुशासन शिविर एक बात साफ कर गया अब ग्रामीण सिर्फ चुपचाप आवेदन देने वाले लोग नहीं रहे, वे व्यवस्था को समझते हैं,राजनीति को पहचानते हैं और व्यंग्य के जरिए अपनी बात रखने का हुनर भी सीख चुके हैं,इन मांगों में हास्य जरूर था,लेकिन उनके पीछे छिपी नाराजगी और व्यवस्था पर कटाक्ष भी उतना ही गहरा था,कहीं यह प्रचार की राजनीति पर सवाल था,कहीं बढ़ती गर्मी और असमान जीवनशैली पर चिंता,तो कहीं सरकारी दफ्तरों की सुस्त व्यवस्था पर जनता की चुटकी,अब देखना यह है कि सरकार इन मांगों को मजाक समझकर फाइल में दबा देती है या फिर इन्हें जनता के बदलते सोच और बढ़ती जागरूकता का संकेत मानती है, फिलहाल लटमा का यह शिविर बता गया कि गांव की जनता अब सिर्फ समस्याएं नहीं गिनातीज्वह व्यंग्य में भी पूरी राजनीति समझा देती है।

बिछड़ों को मिला अपनों का साथ,जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की पहल से वृद्ध दंपत्ति की भावुक घर वापसी

वृद्धाश्रम से घर तक पहुंची रिश्तों की डोर...

-संवाददाता-

सूरजपुर,29 मई 2026
(घटती-घटना)।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की संवेदनशील पहल ने एक बिछड़े परिवार को फिर से जोड़ने का काम किया है,पारिवारिक मतभेदों के कारण वृद्धाश्रम में रहने को मजबूर हुए बुजुर्ग दंपत्ति को आखिरकार अपनों का साथ फिर से मिल गया,यह भावुक पहल केवल कानूनी सहायता तक सीमित नहीं रही,बल्कि टूटते रिश्तों को जोड़ने और पारिवारिक मूल्यों को पुनर्जीवित करने का उदाहरण बन गई।

अपनों को संतान मानकर बिताया जीवन,फिर छोड़ना पड़ा घर

मूल रूप से पटना थाना क्षेत्र निवासी श्री शंकर प्रसाद और उनकी पत्नी की अपनी कोई संतान नहीं है,परिवार में पांच भाइयों के बीच उन्होंने अपने भाइयों के बच्चों को ही संतान मानकर जीवन बिताया। लेकिन समय के साथ पारिवारिक मतभेद बढ़ते गए और परिस्थितियां ऐसी बनीं कि बुजुर्ग दंपत्ति को अपना घर छोड़कर सूरजपुर के तिलसिवा स्थित स्नेह सम्बल वृद्धाश्रम में आश्रय लेना पड़ा।

डीएलएसए की पहल से बदली स्थिति

25 मई 2026 को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सूरजपुर की सचिव पायल टोपनो ने वृद्धाश्रम का आकस्मिक निरीक्षण किया,निरीक्षण के दौरान जब उन्हें बुजुर्ग दंपत्ति की स्थिति और पारिवारिक पृष्ठभूमि की जानकारी मिली तो उन्होंने तत्काल मामले को गंभीरता से लेते हुए पहल शुरू की,प्राधिकरण द्वारा परिवारजनों से संपर्क कर उन्हें न केवल कानूनी जिम्मेदारियों बल्कि नैतिक कर्तव्यों के बारे में भी समझाया गया,लगातार काउंसिलिंग और संवाद का सकारात्मक परिणाम सामने आया।

परिजन स्वयं पहुंचे वृद्धाश्रम

प्राधिकरण की पहल के बाद श्री शंकर प्रसाद के छोटे भाई श्री कृष्णा,उनकी पत्नी श्रीमती सुमित्रा और उनका पुत्र स्वयं वृद्धाश्रम पहुंचे,उन्होंने बुजुर्ग दंपत्ति को ससम्मान घर वापस ले जाने की सहमति दी,वर्षों बाद अपनों को सामने देखकर बुजुर्ग दंपत्ति की आंखें खुशी से नम हो उठीं,यह दृश्य वहां मौजूद लोगों के लिए बेहद भावुक और प्रेरणादायक रहा।

वरिष्ठ नागरिकों के अधिकारों पर भी हुई जागरूकता

इस अवसर पर तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश डायमंड कुमार गिलहरें एवं व्यवहार न्यायाधीश सुश्री हिमांशी सर्राफ विशेष रूप से उपस्थित रहीं,न्यायाधीशों ने परिवारजनों को वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल के महत्व के बारे में समझाया और उन्हें इस कदम के लिए प्रोत्साहित किया,कार्यक्रम में नालसा की वरिष्ठ नागरिकों के लिए विधिक सेवाएं योजना 2016 तथा माता-पिता एवं वरिष्ठ नागरिक भरण-पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 के प्रावधानों की जानकारी भी दी गई।

समाज के लिए प्रेरणादायक पहल

कार्यक्रम में स्नेह सम्बल वृद्धाश्रम की अधीक्षिका पायल गुप्ता,आश्रम स्टाफ,वरिष्ठजन और पैरा लीगल वालंटियर्स भी मौजूद रहे,यह पहल एक बार फिर यह संदेश देती है कि कानून केवल सजा देने का माध्यम नहीं, बल्कि टूटते रिश्तों को जोड़ने और मानवीय संवेदनाओं को बचाए रखने का भी जरिया बन सकता है।

CMYK

बॉस की बेटी पर आया बाबू भैया का दिल

12 साल की डेटिंग और पेड़ों की छांव में ब्याह,बेहद फिल्मी है बाबू भैया की लव स्टोरी...

अपनी पीढ़ी के सबसे बेहतरीन अभिनेताओं में से एक, परेश रावल अपनी पत्नी स्वरूप संपत के साथ अपनी निजी जिंदगी को सादा रखना पसंद करते हैं। परेश रावल बॉलीवुड का एक ऐसा नाम हैं,जिनकी जबरदस्त एक्टिंग को किसी और पहचान की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनकी एक्टिंग खुद ही अपनी कहानी बयां करती है। अपनी पहली फिल्म से लेकर उसके बाद की हर फिल्म में, परेश ने हमेशा यह पक्का किया है कि वे अपनी एक्टिंग के स्तर को हर बार और भी ऊंचा उठाएं। हालांकि,अपने तारीफ के काबिल एक्टिंग करियर के उलट,उन्होंने अपनी निजी जिंदगी को हमेशा लाइमलाइट से दूर, एक गरिमापूर्ण दायरे में रखा है। जो लोग नहीं जानते, उन्हें बता दें कि इस एक्टर की शादी पूर्व मिस इंडिया और पुराने जमाने की थिएटर एक्ट्रेस, स्वरूप संपत से हुई है।

कॉलेज में हो गए थे संपत के दीवाने

अपने कॉलेज के दिनों में, परेश रावल और स्वरूप संपत थिएटर और एक्टिंग के बहुत बड़े दीवाने थे। इसलिए किस्मत ने कुछ ऐसा खेल रचा कि वे दोनों एक स्टेज परफॉर्मेंस के दौरान ही एक-दूसरे से मिले। यह एक इंटर-कॉलेज नाटक था,और स्टेज पर परेश की जबरदस्त परफॉर्मेंस देखकर स्वरूप पूरी तरह से मुग्ध हो गईं। यही नहीं, परफॉर्मेंस के बाद वह परेश से मिलने और उन्हें बधाई देने के लिए बैकस्टेज भी गईं। कई साल बाद एक इंटरव्यू में,स्वरूप ने उस यादगार दिन के बारे में खुलकर बात की।

बाबू भैया को हुआ पहली नजर का प्यार

खैर,परेश को भी पहली नजर में ही प्यार हो गया था; जैसे ही उन्होंने ऑडिटोरियम में कदम रखा, गुलाबी साड़ी पहने स्वरूप को देखते ही वह पूरी तरह से उनके प्यार में डूब गए। स्वरूप के लिए परेश का प्यार इतना गहरा था कि उन्होंने सीधे-सीधे यह ऐलान कर दिया कि अगर वह शादी करेंगे, तो सिर्फ स्वरूप से ही करेंगे।

दोस्त ने दी थी स्वरूप का पीछा ना करने की सलाह

एक इंटरव्यू में,परेश ने उस पल को याद किया जब पहली बार उनकी नजर अपनी प्रेमिका पर पड़ी थी। उन्होंने बताया कि उनके दोस्तों ने उन्हें स्वरूप के पीछे न पड़ने की सलाह दी थी,क्योंकि वह परेश के बॉस की बेटी थीं और उस समय परेश उन्हीं के अधीन काम कर रहे थे। उन्होंने बताया,मैं कुछ इस तरह का था कि ये लड़की मेरी पत्नी बनेगी। मेरे दोस्त महेंद्र जोशी मेरे साथ थे। उन्होंने मुझसे कहा तुझे पता है तू जिस कंपनी में काम कर रही है हमारे बॉस की बेटी है। तो मैंने बोला, किसी की भी बेटी हो,बहन हो,मां हो, मैं इसके साथ शादी करूंगी।

इसके बाद,वे दोनों अक्सर एक-दूसरे से मिलने लगे,और उनकी दोस्ती जल्द ही एक गहरे साथ और प्यार में बदल गई। उन्होंने बारह साल तक एक-दूसरे को डेट किया और कभी भी अपने रिश्ते को लेकर कम गंभीर होने की उम्मीद नहीं छोड़ी। हालांकि, एक खास घटना ऐसी हुई जिसने स्वरूप का दिल पहले से भी कहीं ज्यादा जीत लिया।

मिस इंडिया बनी थीं स्वरूप

उस समय,उनके पिता ने उन्हें अपनी मर्जी से मिस इंडिया प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए प्रोत्साहित किया था, हालांकि स्वरूप खुद इसके लिए बहुत ज्यादा उत्सुक नहीं थीं। लेकिन, जब उन्होंने यह बात परेश को बताई, तो वह यह सुनकर हैरान रह गईं कि परेश ने कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए,वह उन्हें प्रतियोगिता स्थल तक ले जाने के लिए इंतजार करेंगे। अटूट साथ के इस वादे ने स्वरूप को पूरी तरह से भाव-विभोर कर दिया, जिसका नतीजा यह हुआ कि उन्होंने प्रतियोगिता में हिस्सा लिया और बाद में 1979 में मिस इंडिया का ऐतिहासिक खिताब अपने नाम किया।

ऐसे किया स्वरूप को प्रपोज

अपने इस अनोखे रिश्ते के साथ, परेश रावल ने आखिरकार अपनी प्रेमिका, स्वरूप संपत से सबसे जरूरी सवाल पूछने का फैसला किया। स्वरूप को पहली बार देखते समय उनके मन में जो विचार आए थे, ठीक वैसे ही इस बार भी उन्होंने यह पक्का किया कि उनका प्रपोजल हमेशा की तरह एकदम सीधा-सादा हो। वह स्वरूप के पास गए और बिना किसी देरी की मांग सुने, उनसे शादी करने की अपनी इच्छा जाहिर कर दी। अपने प्रपोजल के बारह साल बाद, इस जोड़े ने शादी कर ली।

अनोखे तरीके से की थी शादी

इतने सालों की प्रेम कहानी के बाद, इस कपल की शादी बेहद असाधारण और अनोखी थी। दोनों ने 1987 में एक बेहद गुपचुप समारोह में शादी की थी,जिसके बारे में उनके परिवार वालों के अलावा लगभग किसी को भी पता नहीं था। लेकिन,उनकी शादी की एक और भी ज्यादा अनोखी बात यह थी कि उन्होंने अपनी शादी की कसमें बड़े-बड़े पुराने पेड़ों की छांव में एक अनोखे अंदाज में खाई थीं; वहां न तो कोई अग्नि प्रज्वलित की गई थी और न ही कोई मंडप सजाया गया था। परेश और स्वरूप की शादीशुदा जिंदगी आज भी उतनी ही खुशहाल और मजेदार है, जितनी उनकी पहली मुलाकात के समय थी। इसके अलावा,अब यह जोड़ा अपने बेटों अनिरुद्ध और आदित्य के गर्वित माता-पिता भी है; इन दोनों ने भी अपने माता-पिता की तरह ही रचनात्मक क्षेत्र में अपना करियर चुना है। आज की बात करें तो, शादी के 40 साल बाद भी, इस जोड़े ने हर हाल में एक-दूसरे का साथ निभाने की पूरी कोशिश की है, और जिंदगी के हर उतार-चढ़ाव का मिलकर सामना किया है।

ऊर्फी जावेद ने साझा किया संघर्ष का सफर,बताया कैसे मुश्किलों से बदल गई जिंदगी

टीवी एक्ट्रेस, होस्ट और सोशल मीडिया पर्सनैलिटी ऊर्फी जावेद ने हाल ही में अपने जीवन के संघर्षपूर्ण दौर और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में शुरुआती कठिनाइयों को लेकर खुलकर बात की। उन्होंने बताया कि सोशल मीडिया के जरिए पहचान मिलने से पहले उनका टेलीविजन करियर बेहद चुनौतीपूर्ण रहा और उन्हें कई आर्थिक व व्यक्तिगत परेशानियों का सामना करना पड़ा। एक पॉडकास्ट बातचीत के दौरान, ऊर्फी जावेद ने अपने शुरुआती दिनों के संघर्षों को याद किया। यह बातचीत उन्होंने अभिनेत्री सोहा अली खान के साथ की,जिसमें उन्होंने अपनी जिंदगी के उन पहलुओं पर प्रकाश डाला जो अब तक लोगों के सामने कम ही आए थे। ऊर्फी ने बताया कि उनके जीवन में कई ऐसे मोड़ आए जब उन्हें पैसों की तंगी का सामना करना पड़ा। बावजूद इसके,उन्होंने कभी अपने सपनों को छोड़ा नहीं। उन्होंने कहा कि उनके भीतर हमेशा एक मजबूत इच्छा थी कि वे एक दिन मुंबई में सफल होकर एक बेहतर और आरामदायक जीवन जी सकें। उन्होंने अपने कठिन अतीत का जिक्र करते हुए बताया कि वे एक ऐसे माहौल से निकली हैं जहां उन्हें कई तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ा। उन्होंने कहा कि वह अपने कथित रूप से दुर्व्यवहार करने वाले पिता से बचने के लिए घर छोड़कर चली गई थीं। इसके बाद उन्होंने दिल्ली में अपने जीवन को नए सिरे से शुरू किया,जहां उन्होंने कॉल सेंटर में काम किया और साथ ही ट्यूशन क्लास लेकर अपना खर्च चलाया। इस दौरान उनके सामने कई आर्थिक और भावनात्मक चुनौतियां थीं,लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। ऊर्फी ने बताया कि उन कठिन परिस्थितियों में भी उन्हें अपने सपनों पर पूरा भरोसा था और वह हमेशा मानती थीं कि एक दिन वह मुंबई में कुछ बड़ा करेंगी। मुंबई आने के बाद उन्होंने टेलीविजन इंडस्ट्री में कदम रखा,लेकिन शुरुआती दौर में उन्हें अपेक्षित सफलता नहीं मिली। कई बार असफलताओं और सीमित अवसरों के बावजूद उन्होंने अपने प्रयास जारी रखे। बाद में सोशल मीडिया ने उनके करियर को एक नई दिशा दी और उन्हें व्यापक पहचान मिली। उनकी अनोखी शैली और बेबाक अंदाज ने उन्हें इंटरनेट पर एक अलग पहचान दिलाई, जिसके बाद वह एक चर्चित पर्सनैलिटी बन गईं। ऊर्फी जावेद का यह सफर इस बात को दर्शाता है कि कठिन परिस्थितियों और संघर्षों के बावजूद यदि व्यक्ति में आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प हो तो वह अपने सपनों को हासिल कर सकता है।

अली फज़ल और सोनाली बेंद्रे की राख 12 जून को होगी रिलीज़

अली फज़ल और सोनाली बेंद्रे अभिनीत इन्वेस्टिगेटिव थ्रिलर राख की रिलीज़ डेट आ गई है। यह शो 12 जून को प्राइम वीडियो पर रिलीज़ होगा। राख में आमिर बशीर की भी अहम भूमिका है,जिसका निर्देशन और एग्जीक्यूटिव प्रोडक्शन प्रोसित रॉय ने किया है। शो के आधिकारिक सारांश में कहा गया है,राख एक इन्वेस्टिगेटिव ड्रामा है जो एक अपराधी के दिमाग और रोज़मर्रा की जिंदगी की सतह के नीचे छिपे अंधेरे का गहरा अध्ययन करता है। जब दो टीनएजर बिना कोई निशान छोड़े गायब हो जाते हैं, तो एक करीबी परिवार टूट जाता है और पूरा शहर दहशत में आ जाता है। एक ज़बरदस्त इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर सच का पता लगाने के लिए देशव्यापी तलाशी अभियान शुरू करता है लेकिन वह जितना गहरा जाता है, यह केस उसे हिंसा और इंसानी बुराई की दुनिया में उतना ही खींचता जाता है। शो से फैंस क्या उम्मीद कर सकते हैं, इस पर प्रोसित रॉय ने एक प्रेस नोट में कहा, ख़ उन प्रोजेक्ट्स में से एक रहा है जो मेरे लिए सबसे ज़्यादा रचनात्मक रूप से संतोषजनक और भावनात्मक रूप से गहन रहे हैं, क्योंकि अपने मूल में, यह सिर्फ़ एक क्राइम थ्रिलर से कहीं ज़्यादा है। राख के बारे में जिस बात ने मुझे सबसे ज़्यादा उत्साहित किया, वह था एक रोमांचक तलाशी अभियान के थ्रिल को, ट्रॉमा और इंसानी स्वभाव की गहरी बुराइयों की बेबाक पड़ताल के साथ मिलाने का मौका। अनुषा और संदीप ने एक ऐसी दुनिया बनाई है जिस पर बहुत बारीकी से रिसर्च की गई है, जिसमें कई परतें हैं, और जो नैतिक दुविधाओं से भरी है। अली एक शांत लेकिन ज़बरदस्त तेवर लाते हैं जो पूरी कहानी को मज़बूती देता है, जबकि सोनाली और आमिर अपने किरदारों को इतनी शिद्दत से निभाते हैं कि हर पल असली लगता है।

नागिन 7 ग्रैंड फिनाले प्रोमो में अनीता हसनंदानी और तेजस्वी प्रकाश की एंट्री की चर्चा,प्रियंका चाहर चौधरी संग

लंबे इंतज़ार के बाद, एकता कपूर का शो नागिन 7 आखिरकार पिछले दिसंबर में कलर्स टीवी पर एयर होना शुरू हो गया। पॉपुलर फ्रैंचाइज़ी के सीज़न 7 में प्रियंका चाहर चौधरी लीड रोल में हैं, और ऐसी खबरें हैं कि शो जल्द ही खत्म होने वाला है। सोशल मीडिया पर एक प्रोमो वायरल हुआ है जिसमें दावा किया गया है कि नागिन 7 का ग्रैंड फिनाले एपिसोड 6 और 7 जून को एयर किया जाएगा। प्रोमो में यह भी दिखाया गया है कि अनीता हसनंदानी और तेजस्वी प्रकाश, जिन्होंने पिछले सीज़न में नागिन का रोल किया है, ग्रैंड फिनाले एपिसोड में नज़र आएंगी। खैर,अभी यह पता नहीं चला है कि यह फैन-मेड प्रोमो है या ऑफिशियल,क्योंकि इसे कलर्स टीवी या बालाजी टेलीफिल्म्स ने शेयर नहीं किया है। प्रोमो पर रिएक्शन देते हुए,एक नेटिज़न्स ने ट्वीट किया,सब लोग क्यों मान रहे हैं कि यह चैनल का रिलीज़ किया गया ऑफिशियल प्रोमो है? यह फैन-मेड है, दोस्तों। इस हफ़्ते का प्रोमो भी अभी तक रिलीज़ नहीं हुआ है, तो अगले हफ़्ते का प्रोमो कैसे आ जाएगा? यकीन करने से पहले प्लीज़ वेरिफ़ाई कर लें।

पद्मिनी कोल्हापुरी ने रणवीर सिंह का समर्थन किया

एक्टर रणवीर सिंह का फरहान अख्तर की फिल्म डॉन 3 से बाहर होना चर्चा का विषय बना हुआ है। सोमवार को,फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉइज ने फरहान की शिकायत के बाद रणवीर के खिलाफ नॉन-कोऑपरेशन डायरेक्टिव जारी किया,जिसमें दावा किया गया था कि रणवीर के फिल्म से बाहर होने से लगभग 45 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ। पंडित के मुताबिक, यह मामला 11 अप्रैल का है, जब फरहान ने रणवीर के खिलाफ फ्वाईस में शिकायत दर्ज कराई थी।

पद्मिनी ने कहा, सीआईएनटीएए को गर्व है कि रणवीर सिंह हमारे मेंबर हैं। जब भी उन्हें हमारी ज़रूरत होती है,हम उनके साथ और उनके लिए खड़े रहते हैं। यह पहले से ही पब्लिक डोमेन में है,इसलिए मैं इस पर और कमेंट नहीं करना चाहती। हम उनके लिए,उनके साथ हैं। अगर उन्हें कभी हमारी ज़रूरत होगी,तो हम रणवीर सिंह के साथ हैं। सोमवार को बाद में,रणवीर के ऑफिशियल स्पोक्सपर्सन ने इस विवाद और नॉन-कोऑपरेशन डायरेक्टिव पर बात की। एक बयान में, स्पोक्सपर्सन ने कहा,रणवीर सिंह फिल्म इंडस्ट्री और डॉन फ्रेंचाइजी से जुड़े सभी लोगों का बहुत सम्मान करते हैं। डॉन 3 को लेकर हाल के डेवलपमेंट्स के दौरान, उन्होंने जानबूझकर चुप्पी बनाए रखी है, उनका मानना है कि प्रोफेशनल बातचीत और पर्सनल इक्वेशन को डिग्निटी,मैच्योरिटी और आपसी सम्मान के साथ सबसे अच्छे से हैंडल किया जाता है। अभी तक,न तो रणवीर सिंह और न ही फरहान अख्तर ने ऑफिशियली इस विवाद पर बात की है। डॉन फ्रेंचाइजी बॉलीवुड की सबसे पॉपुलर एक्शन-थ्रिलर सीरीज में से एक है। शाहरुख खान के पिछले दो इंस्टॉलमेंट्स में हेडलाइन बनने के बाद,डॉन 3 की घोषणा की गई जिसमें रणवीर सिंह आइकॉनिक रोल में हैं।

खेल समाचार

बीसीसीआई ने आईपीएल में स्मार्ट सनग्लासेस पर लगाया प्रतिबंध

नई दिल्ली,29 मई 2026। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने इंडियन प्रीमियर लीग के बचे हुए मैचों में खिलाड़ियों,सपोर्ट स्टाफ और मैच अधिकारियों के लिए एक अहम सुरक्षा निर्देश जारी किया है। इस निर्देश के तहत अब रिस्ट्रिक्टेड एरिया में स्मार्ट सनग्लासेस के इस्तेमाल या उन्हें पहनकर प्रवेश करने पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है। एसीएसयू ने शुक्रवार को यह निर्णय जारी किया। बोर्ड ने कहा कि हाल के समय में स्मार्ट आईवियर डिवाइस के उपयोग और प्रचार में तेजी देखी गई है, जिनमें लाइव स्ट्रीमिंग,मैसेजिंग और वीडियो कम्युनिकेशन जैसी तकनीकी सुविधाएं मौजूद होती हैं। इसी कारण सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह कदम उठाया गया है। बीसीसीआई द्वारा बीसीसीआई फ्रेंचाइजियों को भेजे गए एडवाइजरी में स्पष्ट किया गया है कि ये हाई-टेक स्मार्ट सनग्लासेस अब प्रतिबंधित इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की श्रेणी में आते हैं। बोर्ड का मानना है कि ऐसे डिवाइस मैच के दौरान गोपनीयता और सुरक्षा मानकों को प्रभावित कर सकते हैं। सूत्रों के अनुसार, यह प्रतिबंध खास तौर पर टूर्नामेंट के अंतिम दो मैचों को ध्यान में रखते हुए लागू किया गया है, ताकि किसी भी तरह की अनधिकृत रिकॉर्डिंग या संचार की संभावना को रोका जा सके। बोर्ड ने सभी टीमों को निर्देश दिया है कि खिलाड़ी, सपोर्ट स्टाफ और मैच ऑफिशियल्स किसी भी स्थिति में इन उपकरणों को स्टेडियम के प्रतिबंधित क्षेत्रों में न लाएं।

वैभव सूर्यवंशी आईपीएल में विराट कोहली के ऐतिहासिक रिकॉर्ड के करीब पहुंचे...

नई दिल्ली,29 मई 2026। भारतीय क्रिकेट के उभरते सितारे और राजस्थान रॉयल्स के विस्फोटक बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने एक बार फिर अपने प्रदर्शन से क्रिकेट जगत को चौंका दिया है। आईपीएल 2026 में लगातार शानदार बल्लेबाजी करते हुए उन्होंने कई बड़े रिकॉर्ड अपने नाम किए हैं और अब वे एक ऐतिहासिक उपलब्धि के बेहद करीब पहुंच गए हैं। वैभव सूर्यवंशी ने इस सीजन में अपनी आक्रामक बल्लेबाजी से न सिर्फ गेंदबाजों को परेशान किया है, बल्कि रिकॉर्ड बुक को भी लगातार बदलते हुए नजर आ रहे हैं। अपनी पारी की पहली गेंद से ही बड़े शॉट खेलने की क्षमता के कारण वे चर्चा का केंद्र बने हुए हैं। हाल ही में उन्होंने वेस्टइंडीज के दिग्गज खिलाड़ी क्रिस गेल के सर्वाधिक छक्कों के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया था, जिससे उनकी आक्रामक शैली और प्रभावशाली बल्लेबाजी का अंदाजा लगाया जा सकता है। अब वे भारतीय स्टार बल्लेबाज विराट कोहली के एक बड़े ऑल-टाइम आईपीएल रिकॉर्ड के और करीब पहुंच गए हैं।

पूजा सिंह ने हाई जंप का 14 साल पुराना नेशनल रिकॉर्ड तोड़ा

भारत की पूजा सिंह ने एशियन अंडर-20 चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है...हाई जंप इवेंट में पूजा ने 14 साल पुराने नेशनल रिकॉर्ड को तोड़कर गोल्ड पर कब्जा जमाया...

हांगकांग,29 मई 2026। भारत की हाई जंप की खिलाड़ी पूजा सिंह ने एशियन अंडर-20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतत लिया है। शुक्रवार को इवेंट के दूसरे दिन गोल्ड मेडल जीतने के साथ ही उन्होंने नेशनल रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। 19 वर्ष की पूजा ने करियर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 1.93 मीटर की कूद लगाई। उन्होंने सहाना कुमारी का 14 साल पुराना 1.92 मीटर का राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ा।

कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए पूजा ने क्वालीफाई किया

इससे पहले उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 1.90 मीटर था जो उन्होंने अप्रैल 2026 में दिल्ली में इंडियन एथलेटिक्स सीरीज मीट में बनाया था। मौजूदा एशियाई चैंपियन पूजा ने पिछले साल दक्षिण कोरिया में महिला ऊंची कूद का गोल्ड मेडल जीता था। इसके साथ ही उन्होंने भारतीय एथलेटिक्स महासंघ का राष्ट्रमंडल खेलों के लिये तय 1.92 मीटर का क्वालीफाइंग मानक भी हासिल कर लिया। खेल मंत्री मंसुख मांडविया ने एक्स पर पूजा की तारीफ करते हुए लिखा...टॉप्स एथलीट पूजा का शानदार प्रदर्शन। एशियाई यू-20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में जीता गोल्ड मेडल। उनकी 1.93 मीटर की छलांग ने राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ दिया है। उनके उज्ज्वल भविष्य के लिए उन्हें शुभकामनाएं।

भारत के खाते में अब तक दो गोल्ड

भारत अब तक चार गोल्ड, दो सिल्वर और दो ब्रॉन्ज जीत चुका है। नितिन गुप्ता ने पुरूषों की 5000 मीटर पैदलचाल में स्वर्ण पदक जीता जबकि अमानत कम्बोज ने महिला चक्का फेंक में पीला तमगा हासिल किया। राहुल जाखड़ ने पुरूषों के डेकाथलन में स्वर्ण जीता। साधना देवी ने महिलाओं की त्रिकूद में और उपकार ने पुरूषों के डेकाथलन में रजत पदक हासिल किया। नीरू पाठक ने महिलाओं की 400 मीटर में कांस्य पदक जीता।

आर्सनल और पीएसजी के बीच चैंपियंस लीग का फाइनल आज

नई दिल्ली,29 मई 2026। यूएफा चैंपियंस लीग 2026 का फाइनल मुकाबला पेरिस सेंट जर्मेन और आर्सनल के बीच 30 मई को बुडापेस्ट के पुस्कास एरेना में खेला जाएगा। पीएसजी डिफेंडिंग चैंपियन है और वे इस बार भी खिताब जीतकर रियल मैड्रिड के बाद लगातार चैंपियंस लीग जीतने वाली दूसरी टीम बनना चाहेगी। दूसरी ओर, आर्सनल की निगाहें अपने पहले चैंपियंस लीग के खिताब पर होंगी।

कार्लसन से हारे वर्ल्ड चैंपियन गुकेश

ओस्लो,29 मई 2026। नॉर्वे शतरंज के चौथे राउंड में शुक्रवार को वर्ल्ड नंबर 1 मैग्नस कार्लसन और मौजूदा वर्ल्ड चैंपियन गुकेश डोम्माराजू के बीच बहुप्रतीक्षित मुकाबले का निर्णायक नतीजा सामने आया। ओस्लो में एक और रोमांचक दिन देखने को मिला,जिसमें काले मोहरों से खेलते हुए, कार्लसन ने एक जटिल खेल में धीरे-धीरे गुकेश को मात दे दी। खेल के अधिकांश समय तक स्थिति संतुलित बनी रही, लेकिन मिडिल-गेम में नॉर्वे के इस सितारे ने अपना मौका भुना लिया। बढ़ते दबाव और समय की कमी के चलते,गुकेश अपनी स्थिति को संभाल नहीं सके, जिससे कार्लसन को एक महत्वपूर्ण क्लासिकल जीत हासिल करने का मौका मिल गया। इस जीत से कार्लसन को टूर्नामेंट की प्वाइंट्स टेबल में अहम अंक मिले,क्योंकि वह अपनी घरेलू सरजमीं पर धीमी शुरुआत से उबरने की कोशिश कर रहे हैं। ओपन टूर्नामेंट के शेष दो गेम कड़ी टक्कर के बाद ड्रॉ पर समाप्त हुए।

पद्मश्री डॉ. सुनीता और डॉ. रामचंद्र गोडबोले से मिले मुख्यमंत्री साय

बस्तर और जनजातीय समाज के लिए चार दशक का समर्पण मानवता की असाधारण मिसाल : सीएम साय

रायपुर,29 मई 2026। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अपने निवास कार्यालय में पद्मश्री से सम्मानित समाजसेवी दंपति डॉ. सुनीता गोडबोले और डॉ. रामचंद्र गोडबोले से आत्मीय मुलाकात कर उनके द्वारा बस्तर और जनजातीय समाज के बीच चार दशकों से अधिक समय से किए जा रहे सेवा कार्यों की सराहना की। मुलाकात के दौरान गोडबोले दंपति ने मुख्यमंत्री को बताया कि 'बस्तर और बस्तरवासियों से हमें गहरा प्रेम है। हम गोंडी और हल्बी में उनसे संवाद करते हैं, यही हमारी संस्कृति है और अब हम बस्तर नहीं छोड़ना चाहते हैं।' मुख्यमंत्री साय ने इस आत्मीय भावना को बस्तर,उसकी संस्कृति और जनजातीय समाज के प्रति गहरे समर्पण का प्रतीक बताते हुए कहा कि यह केवल सेवा का विषय नहीं, बल्कि मानवीय आत्मीयता, संवेदनशीलता और सामाजिक प्रतिबद्धता की दुर्लभ मिसाल है।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने गोडबोले दंपति को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि उनका पद्मश्री सम्मान केवल व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं,बल्कि पूरे प्रदेश,विशेष रूप से बस्तर,जनजातीय समाज और बस्तरवासियों के सम्मान का विषय है। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि सेवा,समर्पण और मानवता की मिसाल बने गोडबोले दंपति का सम्मानित होना छत्तीसगढ़ के लिए गौरव का क्षण है। उन्होंने कहा कि डॉ. सुनीता गोडबोले और डॉ. रामचंद्र गोडबोले ने चार दशकों से अधिक समय तक बस्तर और अबूझमाड़ जैसे दुर्गम क्षेत्रों में समर्पण और संवेदनशीलता के साथ कार्य कर यह उदाहरण प्रस्तुत किया है कि सेवा का वास्तविक अर्थ समाज के सबसे जरूरतमंद व्यक्ति तक अपनत्व,विश्वास और मानवीय संवेदना पहुंचाना है। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि गोडबोले दंपति ने जनजातीय समाज तक पहुंचकर निःशुल्क उपचार उपलब्ध कराया,कुपोषण,टीबी,मलेरिया, पीलिया और अन्य गंभीर बीमारियों के प्रति जागरूकता फैलायी तथा शिक्षा और नशामुक्ति जैसे विषयों पर उल्लेखनीय कार्य किया। उन्होंने कहा कि कठिन परिस्थितियों और सीमित संसाधनों के बावजूद जनजातीय समाज के बीच बने रहना और सेवा करते रहना असाधारण समर्पण का उदाहरण है। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि गोडबोले दंपति केवल चिकित्सक के रूप में नहीं,बल्कि जनजातीय समाज के आत्मीय सहयोगी के रूप में कार्य करते रहे हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि नक्सलवाद के कठिन दौर में भी गोडबोले दंपति ने सेवा का मार्ग नहीं छोड़ा और मानवता को सर्वोपरि रखते हुए जनजातीय समाज के बीच लगातार कार्य करते रहे। उन्होंने कहा कि जब भय और असुरक्षा का वातावरण था, तब भी इनका बस्तर और उसके लोगों के प्रति विश्वास और प्रतिबद्धता कमजोर नहीं हुई। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह दर्शाता है कि इस प्रदेश, इसकी संस्कृति और जनजातीय समाज के प्रति उनका प्रेम कितना गहरा और आत्मीय है। उन्होंने कहा कि सेवा का वास्तविक अर्थ कठिन परिस्थितियों में समाज के साथ खड़े रहने से सिद्ध होता है और गोडबोले दंपति ने इसे अपने जीवन से प्रमाणित किया है। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि उन्हें यह देखकर विशेष प्रसन्नता हुई कि गोडबोले दंपति को बस्तर और छत्तीसगढ़ की संस्कृति की गहरी समझ है। उन्होंने कहा कि वे केवल यहां कार्य नहीं कर रहे, बल्कि स्थानीय संस्कृति, परंपराओं और जीवनशैली में पूरी तरह रच-बस गए हैं तथा उसे आत्मसात किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि गोंडी और हल्बी जैसी स्थानीय भाषाओं में संवाद स्थापित करना इस बात का प्रमाण है कि उन्होंने लोगों के बीच विश्वास, अपनत्व और आत्मीयता का मजबूत रिश्ता बनाया है। यही कारण है कि आज वे स्वयं कहते हैं कि अब बस्तर छोड़ने का उनका मन नहीं है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि वनवासी कल्याण आश्रम से उनका स्वयं का जुड़ाव रहा है और वे जानते हैं कि आश्रम के संस्कार सेवा, समर्पण और समाज के प्रति आत्मीयता की भावना को मजबूत करते हैं। उन्होंने कहा कि आश्रम की यात्रा और उसके मूल उद्देश्य समाज के अंतिम व्यक्ति तक संवेदनशीलता और आत्मीय सहयोग पहुंचाने के विचार से जुड़े हैं तथा यह कार्य समाज में सकारात्मक परिवर्तन की मजबूत नींव तैयार करता है। मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने गोडबोले दंपति से संवाद करते हुए बस्तर के विकास के लिए राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे सूक्ष्म स्तर के प्रयासों और कार्ययोजना की जानकारी भी साझा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार बस्तर में विकास और विश्वास की नीति पर गंभीरता से कार्य कर रही है ताकि सुरक्षा के साथ-साथ लोगों तक शासन, सेवाएं और अवसर भी पहुंचें। उन्होंने कहा कि सरकार सुरक्षा व्यवस्था को केवल सुरक्षा तक सीमित नहीं रखना चाहती, बल्कि उसे जनसेवा से जोड़ते हुए व्यापक सामाजिक परिवर्तन का माध्यम बना रही है।

कांग्रेस में बढ़ी सियासी हलचल...भूपेश बघेल बोले हाईकमान ने इस्तीफा नहीं मांगा

रायपुर,29 मई 2026। कर्नाटक की राजनीति में आए अचानक भूचाल और मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के अपने पद से इस्तीफे के एलान के बाद, छत्तीसगढ़ के सियासी गलियारों में एक बार फिर पुराना 'ढाई-ढाई साल का फॉर्मूला' चर्चाओं के केंद्र में आ गया है। इस बड़े राजनैतिक घटनाक्रम ने छत्तीसगढ़ में साल 2018 के बाद कांग्रेस शासन के दौरान चली लंबी अंदरूनी खींचतान और सत्ता परिवर्तन की दबी हुई बहसों को दोबारा जिंदा कर दिया है। कर्नाटक में हुए इस बड़े फेरबदल के बाद छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और वर्तमान भाजपा सरकार के मंत्रियों के बीच जुबानी जंग का एक नया दौर शुरू हो गया है।

पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बड़ा बयान, कहा...हाईकमान ने कभी नहीं मांगा इस्तीफा

इस पूरे मामले पर छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए रायपुर में मीडिया से खुलकर बात की। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व (हाईकमान) ने उनसे उनके पांच साल के कार्यकाल के दौरान कभी भी इस्तीफा देने को नहीं कहा था। बघेल ने पुरानी यादें ताजा करते हुए बताया कि जब उन्होंने साल 2018 में मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी, तब पहले ही दिन से मीडिया और राजनीतिक गलियारों में यह सवाल तैर रहा था कि क्या वह केवल ढाई साल के लिए इस कुर्सी पर बैठे हैं।

विपक्ष के भ्रम और हाईकमान के आदेश को लेकर बघेल ने दी सफाई

भूपेश बघेल ने अपनी निष्ठा और पार्टी अनुशासन का हवाला देते हुए कहा कि उन्होंने मुख्यमंत्री बनने के पहले दिन ही यह साफ कर दिया था कि जिस वक्त भी पार्टी हाईकमान का एक फोन आ जाएगा,वह तत्काल प्रभाव से अपने पद से इस्तीफा दे देंगे। उन्होंने भाजपा पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि पूरे पांच साल के कार्यकाल के दौरान उन्हें केंद्रीय नेतृत्व से हटने का ऐसा कोई निर्देश या संकेत नहीं मिला। बघेल के अनुसार,विपक्ष (भाजपा) ने केवल सरकार को अस्थिर दिखाने और जनता के बीच भ्रम का माहौल पैदा करने के लिए लगातार 'ढाई-ढाई साल' के इस कथित फॉर्मूले का दुष्प्रचार किया था।

भाजपा का पलटवार, वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कांग्रेस को घेरा

भूपेश बघेल के इस बयान पर छत्तीसगढ़ के मौजूदा वित्त मंत्री और भाजपा के कद्दावर नेता ओपी चौधरी ने जोरदार पलटवार किया है। ओपी चौधरी ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ की जनता ने कांग्रेस के भीतर चले इस भीषण सत्ता संघर्ष को बेहद करीब से और खुलकर देखा है। उनके मुताबिक,यह कोई छिपा हुआ सच नहीं है कि किस तरह तत्कालीन सरकार के दौरान दो बड़े नेताओं के बीच कुर्सी को लेकर खींचतान चलती रही और पूरी सरकार दो गुटों में बंटकर रह गई थी, जिसका सीधा नुकसान राज्य के विकास को उठाना पड़ा।

जिम्मेदारी का फैसला हाईकमान करता है : टीएस सिंहदेव

भूपेश बघेल के इस बयान पर पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने कहा कि कई बातें बंद कमरे में होती हैं और उनकी मर्यादा रखना सभी का राजनीतिक दायित्व है। उन्होंने कहा कि किसे क्या जिम्मेदारी मिलेगी, यह फैसला हाईकमान करता है।

अवैध संबंधों के शक पर बौखलाई पत्नी...सोते पति पर हंसिए से हमला,काट डाला निजी अंग,महिला गिरफ्तार

बिलासपुर,29 मई 2026। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले के चकरभाठा क्षेत्र से एक बेहद चौंकाने वाली घटना सामने आई है। घरेलू कलह और अवैध संबंधों के शक में एक महिला ने रात में सो रहे अपने पति पर हंसिए से हमला कर उसका निजी अंग काट दिया। गंभीर रूप से घायल युवक को तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया,जहां उसका इलाज जारी है।

शराब के नशे में घर लौटा पति : पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, आरोपी महिला द्रोपती बाई और उसके पति राजेश कौशिक के बीच लंबे समय से पारिवारिक विवाद चल रहा था। राजेश पेशे से राजमिस्त्री है। महिला को अपने पति के किसी अन्य महिला से संबंध होने का संदेह था, जिसके कारण दोनों के बीच अक्सर विवाद होता रहता था। बताया जा रहा है कि घटना वाली रात राजेश शराब के नशे में घर पहुंचा था। इसी बात को लेकर पति-पत्नी के बीच कहासुनी हुई। विवाद के बाद राजेश सो गया, लेकिन पत्नी का गुस्सा शांत नहीं हुआ।

आधी रात को उठाया खौफनाक कदम : रात करीब 1 से 2 बजे के बीच महिला ने घर में रखे हंसिए से अपने पति पर हमला कर दिया। हमले में राजेश गंभीर रूप से घायल हो गया। अचानक हुए इस हमले से घर में अफरा-तफरी मच गई। घटना के समय घर में उनका नाबालिग बेटा और एक रिश्तेदार महिला भी मौजूद थी। शोर सुनकर परिजन मौके पर पहुंचे और घायल को तत्काल अस्पताल ले जाया गया। घायल युवक को गंभीर अवस्था में बिलासपुर के सिम्स अस्पताल में भर्ती कराया गया है। चिकित्सकों की निगरानी में उसका उपचार जारी है। परिजन कटे हुए अंग को भी अपने साथ अस्पताल लेकर पहुंचे थे,ताकि चिकित्सकीय प्रक्रिया में मदद मिल सके।

पति की हरकतों से परेशान थी पत्नी : पुलिस पूछताछ में सामने आया है कि महिला अपने पति की शराब पीने और मारपीट की आदतों से परेशान थी। उसे पति के किसी अन्य महिला के साथ संबंध होने का भी शक था। शुरुआती जांच में पारिवारिक तनाव और अविश्वास को घटना की प्रमुख वजह माना जा रहा है।

राष्ट्रीय आम महोत्सव : राज्यपाल रमेन डेका ने किया उद्घाटन

कहा...छत्तीसगढ़ में मैंगो टूरिज्म की है अपार संभावनाएं...

रायपुर,29 मई 2026। आम केवल एक फल नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति, कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण आधार है। किसानों को पारंपरिक खेती के साथ आधुनिक तकनीकों को अपनाकर आम उत्पादों को बडे रूप में विकसित करने के लिए आगे बढ़ना चाहिए।

राज्यपाल रमेन डेका आज इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर में आयोजित राष्ट्रीय आम महोत्सव के उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। समारोह की अध्यक्षता मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने की। राज्यपाल ने अपने संबोधन में कहा कि भारत विश्व में आम उत्पादन में अग्रणी है और देश में एक हजार से अधिक किस्मों के आम पाए जाते हैं। उन्होंने छत्तीसगढ़ के स्थानीय आमों की विशेषताओं का उल्लेख करते हुए कहा कि प्रदेश के किसानों को उच्च गुणवत्ता वाली किस्मों के उत्पादन से अपनी अलग पहचान बनानी चाहिए। राज्यपाल ने कहा कि इस प्रकार की प्रदर्शनियां और महोत्सव देश के विभिन्न राज्यों से आए आम उत्पादकों को एक-दूसरे की उन्नत खेती पद्धतियों, नई किस्मों और नवाचारों की जानकारी प्राप्त करने का अवसर प्रदान करती है। उन्होंने कहा कि बस्तर, कोण्डागांव, कांकेर और सरगुजा जैसे क्षेत्रों में आम उत्पादन की बहुत संभावनाएं है। महिला स्व-सहायता समूहों के लिए भी इस क्षेत्र में रोजगार और उद्यमिता के व्यापक अवसर मौजूद है। मैंगों टूरिज्म की भी छत्तीसगढ़ में अपार संभावनाएं है। राज्यपाल ने कहा कि आम उत्पादन के साथ-साथ इसके वैल्यू एडिशन पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। इसके लिए कृषि विश्वविद्यालय, छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम को मिलकर कार्य करना चाहिए। डेका ने कहा कि हमारे जीवन को ईको फैंडली बनाना आज की आवश्यकता है। जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न उपायों को अपनाना होगा। उन्होंने एक पेड़ मां के नाम पर लगाने और रेन वाटर हार्वेस्टिंग पर विशेष जोर दिया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि आम फलों का राजा है। आम की पत्तियों और लकड़ियों का भी हमारे जीवन में अत्यधिक महत्व है। हमारे घरों में मांगलिक कार्य होने पर हम आम की पत्तियों से तोरण बनाते है एवं आम की सूखी लकड़ियों का उपयोग हवन एवं पूजा में करते है। इस महोत्सव में 250 से अधिक किस्मों के आम प्रदर्शित किए गए है। मुख्यमंत्री साय ने प्रदेशवासियों को इस महोत्सव का लाभ लेने हेतु प्रेरित किया। प्रदर्शनी में बेर के आकार से लेकर बीजापुर के हाथीझुल जैसे बड़े किस्मों के आम भी उपलब्ध है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधामंत्री नरेन्द्र मोदी के मंशानुरूप किसानों की आय दुगुनी करने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है और आम की खेती भी इस संकल्प को पूरा करने के लिए सहायक सिद्ध होगी।

आम महोत्सव के उद्घाटन पश्चात राज्यपाल डेका और मुख्यमंत्री साय ने आम उत्पादकों द्वारा लगाए गए प्रदर्शनी में आम के विभिन्न किस्मों का अवलोकन किया। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम के अध्यक्ष चंद्रहास चंद्राकर,छत्तीसगढ़ राज्य कृषक कल्याण परिषद के अध्यक्ष सुरेश चंद्रवंशी एवं इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ.गिरीश चंदेल, निदेशक अनुसंधान सेवाएं डॉ. विवेक कुमार त्रिपाठी सहित अन्य विश्व विद्यालयों के कुलपति, अधिष्ठाता, प्राध्यापकगण, किसान एवं बड़ी संख्या में दर्शकगण उपस्थित थे।

कुत्ते के काटने से मौत पर सरकार का जवाब सुन भड़का हाईकोर्ट,अफसरों को चेतावनी

बिलासपुर,29 मई 2026। प्रदेश में आवारा कुत्तों के बढ़ते आतंक और उनके काटने से हो रही मौतों को लेकर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। बिलासपुर निवासी एक पीड़ित पिता की याचिका पर सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने कोर्ट में जवाब देते हुए कहा कि आवारा कुत्ते के काटने से मौत होने पर मुआवजा देने का कोई कानूनी प्रावधान नहीं है। सरकार के इस जवाब पर हाईकोर्ट ने नाराजगी जताते हुए मामले को गंभीर बताया और जिम्मेदार अधिकारियों को सख्त चेतावनी दी। जस्टिस नरेंद्र कुमार व्यास की वेकेशन बेंच ने सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट की ओर से आवारा कुत्तों के प्रबंधन और रोकथाम के लिए जारी दिशा-निर्देशों का हवाला देते हुए सूबे के मुख्य सचिव से शपथ पत्र के साथ जवाब मांगा है। कोर्ट ने पूछा है कि प्रदेश में सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का पालन किस स्तर पर किया जा रहा है और अब तक क्या कदम उठाए गए हैं। मामले की अगली सुनवाई 30 जून को तय की गई है। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार सभी राज्यों के मुख्य सचिवों और संबंधित विभागों को आगामी 7 अगस्त तक हर हाल में अपना शपथ पत्र जमा करना होगा। कोर्ट ने चेतावनी दी कि यदि निर्देशों के पालन में लापरवाही या देरी सामने आई तो संबंधित नगर निगम और प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ सीधे अवमानना की कार्रवाई शुरू की जा सकती है। दरअसल, बिलासपुर निवासी धीरज पारधी ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर बताया कि उनके मासूम बेटे की मौत आवारा कुत्ते के काटने के बाद हुई थी। बेटे की असमय मौत से आहत पिता ने शासन से चार लाख रुपये मुआवजे की मांग की है। इसी मामले में सुनवाई के दौरान सरकार ने मुआवजे का कोई प्रावधान नहीं होने की बात कही, जिसके बाद कोर्ट ने प्रशासनिक जिम्मेदारी और आवारा कुत्तों के नियंत्रण व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाए।

431 किमी पदयात्रा कर सीएम हाउस पहुंचे परिवार ने की न्याय की मांग

वीडियो जारी कर बोला...क्या देनी पड़ेगी जान

रायपुर,29 मई 2026। बलरामपुर जिला अस्पताल में बुखार के दौरान भर्ती की गई महिला की छत से गिरने से मौत मामले में परिवार ने न्याय की गुहार लगाई है। पीड़ित परिवार बलरामपुर से रायपुर 431 किलो मीटर पदयात्रा कर आज सीएम हाउस पहुंचे। यहां अपने साथ हुए घटनाक्रम को लेकर खुलकर बात की। बता दें कि पीड़ित परिवार मामले की जांच व आर्थिक सहायता की मांग को लेकर सीएम हाउस के बाहर बैठे है। बलरामपुर जिला अस्पताल में महिला की मौत का यह मामला 30 अप्रैल की देर रात का है। जिले के ग्राम सेदूर निवासी 58 वर्षीय महिला कौलेश्वरी को बुखार व उल्टी की शिकायत थी। 27 अप्रैल को परिजनों द्वारा उसे बलरामपुर जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था। अस्पताल के महिला मेडिकल वार्ड में उसका इलाज चल रहा था। 30 अप्रैल की रात करीब 12 बजे वह अस्पताल की दूसरी मंजिल

की छत पर पहुंच गई। करीब 10-15 मिनट तक वह छत पर ही टहलती रही। इसके बाद उसने अचानक बिल्डिंग से छलांग लगा दी। इससे महिला नीचे फर्श पर गिरी और गंभीर रूप से घायल हो गई। महिला को तत्काल अस्पताल के कर्मचारियों द्वारा भर्ती किया गया। उसे मेडिकल कॉलेज अस्पताल अंबिकापुर के लिए रेफर कर दिया। एंबुलेंस से अंबिकापुर लाते समय रास्ते में ही उसकी मौत हो गई।

सीएम तक बात पहुंचने निकाली न्याय तिरंगा यात्रा : महिला ने किस कारण से आत्मघाती कदम उठाया, इसका पता फिलहाल नहीं चल सका है। इस घटना को लेकर परिजनों का कहना है कि यह आत्महत्या नहीं है, बल्कि उसे मारा गया है। वहीं मामले में जांच किए बिना ही केस बंद कर दिया गया। पुलिस व जिला प्रशासन से केस की जांच करने की गुहार लगाने के बाद परिवार ने सीएम तक अपनी बात पहुंचाने के लिए 16 मई से तिरंगा न्याय यात्रा निकाली। पूरा परिवार 431 किलो की दूरी तय कर कल 28 मई को सीएम हाउस पहुंचे। पीड़ित परिवार ने एक वीडियो भी जारी किया है। जिसमें अपने साथ हुए घटनाक्रम को बताया है। यूट्यूब में अपलोड किए वीडियो में लिखा कि न्याय की राह कभी आसान नहीं होती, लेकिन आज हम पर जो बीत रहा है, वह बताना जरूरी है।

मिलावटी कोयला सप्लाई करने वाले 3 ट्रक ड्राइवर गिरफ्तार, 115 टन कोयला और 3 ट्रेलर जब्त

जांजगीर-चांपा,29 मई 2026। चांपा पुलिस ने कोयले में मिलावट कर हेराफेरी करने वाले तीन ट्रक ड्राइवरों को गिरफ्तार कर बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 3 ट्रेलर और करीब 115.04 मीट्रिक टन कोयला जब्त किया है। सभी आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है। मिली जानकारी के अनुसार, प्रकाश इंडस्ट्रीज लिमिटेड चांपा के लिए सूरजपुर

जिले के भास्करपारा कोल माइंस से कोयला भेजा गया था। 25 मई को रवाना हुए तीन ट्रेलर 27 मई को प्लांट पहुंचे। जब आरएमएच विभाग में कोयला खाली कराया गया तो उसकी गुणवत्ता संदिग्ध पाई गई। जांच में कोयले में मिलावट की पुष्टि हुई। इस संबंध में पीआईएल चांपा के वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारी सुरेश कुमार ने थाना चांपा में शिकायत दर्ज कराई। मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस अधीक्षक विजय कुमार पाण्डेय के निर्देशन में थाना चांपा पुलिस ने त्वरित जांच शुरू की। पूछताछ के दौरान ट्रक ड्राइवरों ने खुलासा किया कि अमझर स्थित गणेश कोल डिपो में वाहनों से उच्च गुणवत्ता वाला कोयला उतारकर उसकी जगह घटिया कोयला भर दिया गया था,जिसे बाद में प्लांट में सप्लाई किया गया।

जंगल सफारी और नंदनवन जू घूमना अब हुआ महंगा...50% तक बढ़े टिकट के दाम,बच्चों के लगेंगे 100 रुपए

रायपुर,29 मई 2026। नवा रायपुर के नंदनवन जू और जंगल सफारी घूमने जाने वाले पर्यटकों को अब पहले से ज्यादा खर्च करना पड़ेगा। छत्तीसगढ़ शासन के वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग ने जू एंट्री, सफारी राइड और दूसरी सुविधाओं के टिकट रेट में बड़ा बदलाव किया है। नई रेट पॉलिसी के तहत कई श्रेणियों में टिकट दरें औसतन 50% तक बढ़ाई गई हैं, जबकि कुछ कैटेगरी में यह बढ़ोतरी दोगुनी से भी ज्यादा है।

बच्चों का टिकट अब 50 रुपए : पहले 6 से 12 साल तक के बच्चों के लिए जू एंट्री टिकट 25 रुपए लगता था, जिसे अब बढ़ाकर 50 रुपए कर दिया गया है।

बड़ों का टिकट 50 से बढ़कर 100 रुपए : 12 साल से ज्यादा उम्र के पर्यटकों के लिए पहले जू एंट्री टिकट 50 रुपए था। अब इसे बढ़ाकर 100 रुपए कर दिया गया है।

विदेशी पर्यटकों को बड़ा झटका : विदेशी पर्यटकों का टिकट पहले 200 रुपए था, जिसे अब बढ़ाकर 500 रुपए कर दिया गया है।

सीनियर सिटीजन और दिव्यांगजन को राहत : 60 साल से ज्यादा उम्र के वरिष्ठ नागरिक और दिव्यांगजनों की एंट्री पहले की तरह निःशुल्क रहेगी। हालांकि, इसके लिए वैध पहचान पत्र दिखाना जरूरी होगा।

सफारी टिकट में भी बड़ा इजाफा,बच्चों के टिकट में बढ़ोतरी : 6 से 12 साल तक के बच्चों के लिए सफारी टिकट पहले 25 रुपए था। अब नई दरों के अनुसार-

- साधारण बस : 100 रुपए
- एसी बस : 150 रुपए
- इलेक्ट्रिक बस : 175 रुपए कर दिया गया है।
- बड़ों को अब ज्यादा खर्च करना होगा
- 12 साल से ज्यादा उम्र के लोगों के लिए पहले सफारी टिकट 100 रुपए था।

प्रकाशक,मुद्रक,स्वामी अविनाश कुमार सिंह के द्वारा सांई ऑफ्सेट प्रिंटर्स,नमनाकला,संत हरकेवल विद्यापीठ के पास,अम्बिकापुर से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक-अविनाश कुमार सिंह* (पी.आर.बी.कानून के अनुसार संपूर्ण संपादकीय दायित्व के लिए जिम्मेदार)
RNI Reg.No.CHHHIN/2004/15050,डॉक रजिस्टर्ड क्र.:-13/सरगुजा/डीएन/2026-2028-मो. 94062-23001,98265-32611,Email:ghatatighatana11@ gmail.com,Website:www.ghatatighatana.com, (सभी विवादों का न्याय क्षेत्र अम्बिकापुर न्यायालय मान्य होगा)